

बिहार का हेल्थ इंफ्रा होगा हाई-टेक: एम्स पटना संभालेगा सरकारी अस्पतालों की कमान

इमरजेंसी इलाज में नहीं होगा भेदभाव: बिहार के हर सरकारी अस्पताल में लागू होगा एक समान विलनिकल प्रोटोकॉल

प्रातः किरण संवाददाता

पटना । बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नया आयाम देने और हर मरीज की जान बचाने के मकसद से एक बेहद शानदार और दूरगामी फैसला लिया गया है। *अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना* और *स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार* के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस धमाकेदार पहल का सीधा मकसद राज्य के हर जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सरकारी अस्पताल में एम्स जैसा मानकीकृत, आधुनिक और त्वरित इलाज उपलब्ध कराना है।

***गोडौन ऑवर में बरेगा जीवन:**

सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सांप काटने, जलने या जहर फैलने जैसी किसी भी इमरजेंसी में मरीज को रेफर करने के दौरान अब इलाज में



कोई फर्क नहीं आएगा। पूरे बिहार में एक जैसा वैज्ञानिक *क्लीनिकल प्रोटोकॉल* और *ट्रायेज सिस्टम* लागू होगा।

***एम्स पटना बनेगा सुपर हब:**

* एम्स पटना राज्य का शीर्ष तकनीकी संसाधन केंद्र होगा। इसके अलावा बिहार के *13 सरकारी मेडिकल

कॉलेज* रीजनल हब के तौर पर काम करेंगे जो निचले स्तर के अस्पतालों को चौबीसों घंटे मार्गदर्शन देंगे।

***हाई-टेक तकनीकों का धमका:**

अब बिहार के अस्पतालों में *Tele-ICU*, एआई आधारित मेडिकल निपट्य प्रणाली, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और इमरजेंसी

मेडिसिन रजिस्ट्री जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा।* विश्वस्तरीय ट्रेनिंग:* डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, नर्सों और एम्बुलेंस स्टाफ को *सिमुलेशन आधारित ट्रेनिंग* और बेडसाइड टीचिंग से लैस किया जाएगा ताकि वे गंभीर से गंभीर परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें। इस ऐतिहासिक समझौते पर *स्टेट हेल्थ सोसाइटी* की ओर से संयुक्त सचिव *बृंदा लाल * और *एम्स पटना* की ओर से चिकित्सा अधीक्षक *प्रो. डॉ. प्रशांत कुमार सिंह* ने हस्ताक्षर किए। यह पूरा कार्यक्रम *एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल* की गरिमामयी मौजूदगी में संपन्न हुआ। मौके पर डॉ. जयंती श्रीवास्तव, युक्ता सिंह, नीलोत्पल बल और डॉ. दिवेंद्र भूषण जैसे प्रमुख अधिकारी भी गवाह बने।

यह महज एक कागजी समझौता नहीं, बल्कि बिहार के कोने-कोने तक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने वाला परिवर्तनकारी अभियान है। एम्स पटना अपनी पूरी विशेषज्ञता और संसाधनों से राज्य के हर अस्पताल को मजबूत बनाएगा:

प्रो. (ब्रिगेडियर) डॉ. राजू अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक व सीईओ, एम्स पटना

एम्स पटना के साथ यह साझेदारी बिहार के पब्लिक हेल्थ सिस्टम का नक्शा बदल देगी। हमारा लक्ष्य हर सरकारी अस्पताल को इस काबिल बनाना है कि वहां आने वाले हर गंभीर मरीज को तुरंत और सही इलाज मिले।

बृंदा लाल, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) SHS बिहार

खगौल महिला कॉलेज में राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस एवं विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन

प्रातः किरण संवाददाता

दानापुर । खगौल नगर के अंतर्गत महिला कॉलेज, में कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। विज्ञान विभाग के डॉ किरण कुमारी शैलेंद्र कुमार और रुचिका मेहता के द्वारा राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस तथा गृह विज्ञान विभाग के द्वारा सुमन कुमारी ने विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत विविध गतिविधियाँ आयोजित की। राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान विभाग द्वारा छात्राओं के लिए पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता एवं पावरपॉइंट प्रस्तुति प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने रसायन विज्ञान के आधुनिक अनुप्रयोगों, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की उपयोगिता पर आकर्षक पोस्टर एवं प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं, विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर गृह विज्ञान विभाग द्वारा माइम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम



का उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करना था।महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. उषा विद्याधारी ने दोनों कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन छात्राओं के बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों एवं आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में विज्ञान विभाग एवं गृह विज्ञान विभाग के सभी शिक्षकगण तथा छात्राओं का

31 अक्टूबर तक शिक्षकों के तबादले से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान : शिक्षा मंत्री

प्रातः किरण संवाददाता

पटना । शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, ऑनलाइन और शिक्षक हित में संचालित की जा रही है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य 31 अक्टूबर तक स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़े सभी मामलों का निष्पादन कर देना है, ताकि इसके बाद शिक्षक पूरी ऊर्जा के साथ विद्यार्थियों के पठन-पाठन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसी वजह से महिला शिक्षकों को गृह प्रखंड तथा पुरुष शिक्षकों को गृह जिले के भीतर भेजा जा रहा है। गुरुवार को विकास भवन स्थित मदन मोहन सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के समायोजन/समानुपातीकरण के लिए 29 जुलाई से 5 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए। इस अवधि में अधिेश्वर (सरस्वत) 1,06,287 शिक्षकों में से 73,151



शिक्षकों (लगभग 70 प्रतिशत) ने स्वेच्छा से आवेदन किया। वहीं, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 4,259 आवेदन आए। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 7 अगस्त से 9 सितम्बर तक जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर पर गठित स्थापना समितियों द्वारा शिक्षकवार समायोजन सूची का प्रकाशन, प्राप्त आपत्तियों एवं अपीलों का निष्पादन किया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 10 से 14 सितम्बर के बीच किया जाएगा। श्री तिवारी ने बताया कि सामान्य स्थानांतरण के लिए 17 सितम्बर से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस चरण में वे शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे, जो 5 अगस्त तक आवेदन

नहीं कर पाए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों द्वारा आवेदन के दौरान जिन विद्यालयों का विकल्प दिया था है, उनका स्थानांतरण उन्हीं विकल्पों में से किसी एक विद्यालय में किया जाएगा। विकल्प के अतिरिक्त किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न होगी। माननीय शिक्षा मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए शिक्षक संगठनों एवं शिक्षक प्रतिनिधियों को रचनात्मक सुझाव देने तथा शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर संवाद में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया।

प्रदूषण से विनाश संरक्षण से समृद्धि : डॉ. नीना कुमार



पटना । पर्यावरण संरक्षण के निहितार्थ पटना न्यू एरा पब्लिक स्कूल में हरित दिवस का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक, डॉ. (श्रीमती) नीना कुमार द्वारा पौधा रोपण कर एवं सुभिता भट्टाचार्या के स्वागत संबोधन से किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने हरे रंग के परिधान में उपस्थित होकर पर्यावरण संरक्षण से संदर्भित पोस्टर निर्माण, चित्रकला,स्लोलन लेखन का कार्य बड़े ही मनोयोग के साथ किया। नर्सरी एवं एलकेजी के बच्चों ने हल्कलर ग्रीन सॉन्ग पर, प्रथम वर्ग के बच्चों ने सेव द प्लांट पर, द्वितीय वर्ग के बच्चों ने चलो मिलकर.साँप पर तथा तृतीय वर्ग के बच्चों ने मिट्टी की छिट्टी पर समूह नृत्य किया। इसी कड़ी में बताते चलें कि यूकेजी के बच्चों ने ग्रीन डे पर शानदार कविता सुनाई तथा रैप वॉक भी किया। इस अवसर पर प्रदूषण से विनाश तथा संरक्षण से समृद्धि की बात करते हुए विद्यालय के निदेशक, डॉ. (श्रीमती) नीना कुमार ने कहा कि- प्रकृति का संरक्षण करना, अधिकाधिक वृक्ष लाताना, जल एवं ऊर्जा की बचत तथा सिलिंग यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करना प्रत्येक लोगों की जिम्मेदारी है। यह कार्यक्रम काफी प्रभावोत्पादक, प्रेरणादायी एवं ज्ञानवर्धक रहा। धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती अनुपमा नाथ ने किया। मौके पर इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पटना के पूर्व निदेशक डॉ. अरविंद कुमार, उप-प्राचार्य मौसम श्री एवं डॉ. स्नेह सोनी सिंह आदि उपस्थित थीं।

प्रमंडलीय आयुक्त ने लिया स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का लिया जायजा

प्रातः किरण संवाददाता

पटना । स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गाँधी भवन, पटना में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह की तैयारी का जायजा प्रमंडलीय आयुक्त श्री मयंक वरवड़े ने लिया। जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने अबतक हुई तैयारियों के सम्बंध में बताते हुये कहा कि पूरे गाँधी मैदान को 4 जोन में बाँट कर तथा बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुये सारी तैयारी की जा रही है। बैठक में साफ-सफाई, जल निकासी, बैरिकेडिंग, पार्किंग, विद्युत व्यवस्था, परेड एवं पूर्वाभ्यास, येपजल, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा, अग्निशमन की व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, झोंकियों का प्रदर्शन, विधि-

व्यवस्था सहित सभी विन्दुओं पर की जा रही तैयारी की समीक्षा की गई। पूरी भव्यता से आयोजित होगा स्वतंत्रता दिवस का राजकीय समारोह: डीलुप गाँधी मैदान में अस्थायी थाना कार्यरत हो गया है। पूरे गाँधी मैदान एवं आस-पास के क्षेत्र की सी.सी.टी.वी. कैमरे से निगरानी की जा रही है। गाँधी मैदान के चारों ओर बुडको तथा विद्युत विभाग द्वारा संस्थापित हाईड्रामैट लाइट्स को चेक कर लेने को कहा गया। गाँधी मैदान में पर्याप्त संख्या में प्रकाश मीनारों की भी व्यवस्था रहेगी जो समारोह को भव्यता प्रदान करेगा। समारोह में आने वाले लोगों की सुविधा का भी खया जा रहा ध्यान समारोह में भाग लेने वाले लोगों के लिये पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी

समुचित व्यवस्था कर लेने को कहा गया। बारिश की स्थिति में ग्राउंड में जल-जमाव न रहे इसके लिये नूतन राजधानी अंचल एवं पाटलिपुत्रा गाँधी मैदान में अस्थायी थाना कार्यरत हो गया है। पूरे गाँधी मैदान एवं आस-पास के क्षेत्र की सी.सी.टी.वी. कैमरे से निगरानी की जा रही है। गाँधी मैदान के चारों ओर बुडको तथा विद्युत विभाग द्वारा संस्थापित हाईड्रामैट लाइट्स को चेक कर लेने को कहा गया। गाँधी मैदान में पर्याप्त संख्या में प्रकाश मीनारों की भी व्यवस्था रहेगी जो समारोह को भव्यता प्रदान करेगा। समारोह में आने वाले लोगों की सुविधा का भी खया जा रहा ध्यान समारोह में भाग लेने वाले लोगों के लिये पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी

प्राथमिक विद्यालय कंकड़बाग में किया गया ट्रांसमिशन अस्सेसमेंट सर्वे-1

पटना । जिला में ट्रांसमिशन अस्सेसमेंट सर्वे-1 (टास-1) के तहत गुरुवार को कंकरबाग स्थित प्राथमिक विद्यालय, कंकड़बाग में ट्रांसमिशन अस्सेसमेंट सर्वे-1 किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन के निदेशानुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों का रक्त सैपल लिया गयाऔर जांच की गयी. सैपल इकट्ठा करने के बाद क्यू फैंट फिट से फाइलेरिया संक्रमण की जांच की गयी. सर्वे का शुभारंभ जयप्रभा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. शैल सिन्हा द्वारा किया गया. इस अवसर पर वेक्टर बॉन डिजीज सलाहकार कल्याणी, लेब तकनीशियन श्वेता, ए.एन.एम, आशा कार्यकर्ता, स्कूल के शिक्षक और कर्म तथा स्वास्थ्यी संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. जिला में ट्रांसमिशन अस्सेसमेंट सर्वे-1 जिला वेक्टर जनि्त रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र प्रसाद की नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है. मालूम हो कि जिला के बखियापुर, बिहम, नौबतपुर, बाढ़, बेलची, मोकामा, घोसवारी और पटना के शहरी क्षेत्रों में फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टास-1 गतिविधि जिला के सरकारी और निजी स्कूलों में शुरू की गयी है और क्यू फैंट फिट द्वारा ब्लड सैपल की जांच की जा रही है. इसी क्रम में गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय कंकड़बाग के कक्षा 1 और 2 के बच्चों के रक्त के नमूने इकट्ठा किया गया और दोपहर तक 17 बच्चों की जांच की गयी. जानकारी के अनुसार जयप्रभा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 400 बच्चों की जांच करने का लक्ष्य दिया गया है. केंद्र के अधीन पड़नेवाले विद्यालयों में क्रमवार बच्चों की जांच की जाएगी।

अंग्रेजी शराब लोड अनलोड कर रहे तीन वाहन को पकड़ा गया

दानापुर । थाना क्षेत्र के अंतर्गत अशोकपुरी में पुलिस ने अंग्रेजी शराब के खेप लोड अनलोड करते समय तीन वाहनों को बरामद किया।साथ ही विभिन्न कंपनियों की 526.32 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया। लेकिन धंधे से जुड़े लोगों के पकड़े नहीं जाने से जितनी मुह उत्पनी बातें कही जा रही है।साथ पुलिस के छापेमारी पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है।कारण की तीन वाहन मतलब तीन चालकर और धंधे से जुड़े कई लोग भी हागे।बावजूद किसी एक भी गिरफ्तारी नहीं की गई। बताया जाता है कि चार अमस्त की रात पुलिस छापेमारी की थी।एसडीओ वन अजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर दानापुर पुलिस द्वारा लेखानगर के पास अशोकपुरी में छापेमारी की गई अथी। जहां से शराब लोड अनलोड कर रहे एट म्यू एक कार, एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया।साथ ही विभिन्न ब्रांडों के अंग्रेजी शराब, विवर करीब 526.32 लीटर बरामद किया गया।

हजारों युवाओं ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प, प्रेम यूथ फाउंडेशन का अभियान बना जनांदोलन

प्रातः किरण संवाददाता

पटना । प्रेम यूथ फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को युवाओं का जबर्दस्त समर्थन मिल रहा है। फाउंडेशन द्वारा आयोजित संकल्प सभाओं में हजारों छात्र-छात्राओं ने एक स्वर में नशा न करने और समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यातिथि गांधीवादी प्रेम जी का फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने शॉल और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उन्होंने ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा ही देश का भविष्य है। अगर युवा नशे की चपेट में आएं तो विकसित भारत 2047का



सपना अधूरा रह जाएगा।नशा छोड़ जीवन जोड़इह्क का दिया संदेश सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। तम्बाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थों से कैसर, लीवर और मानसिक

बीमारियां होती हैं। छात्र-छात्राओं ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से अपने लिए ना सही अपनों के लिए नशा को ना कहें, नशा मुक्त ही भारत अपना जैसे नारे लगाए। फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर, मोहल्ले और कॉलेज में

अनुमंडलाधिकारी ने अतिक्रमण की सूचना पर जायजा लिया

प्रातः किरण संवाददाता

दानापुर । नगर के अंतर्गत नाला निर्माण में बाधक बने अतिक्रमण की सूचना पर अनुमंडलाधिकारी ने जायजा लिया। साथ ही समस्या के निदान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जल निगम को लेकर बिस्कुट रोड में स्थाई अतिक्रमण के कारण नाला निर्माण में समस्या आ रही है। जिसको लेकर अंचलाधिकारी को यत्थाशीघ्र नोटिस देकर नियमानुसार अतिक्रमण की समस्या का निदान करने का निर्देश दिया गया है। वार्ड संख्या 18 एवं 19 में जल निकासी के स्थल को लेकर विवाद सामने आई है अमीन को उसे जमीन की नापी कर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है।

वाहन चेकिंग के दौरान एक साईबर फ्राड को गिरफ्तार किया

दानापुर । शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने लोदीपुर चांदमारी स्थित छितनावा दानापुर मार्ग में तीन मुहानी के वाहन चेकिंग के दौरान एक साईबर फ्राड को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक स्कार्पियो, 12 मोबाइल,एक लैपटॉप, एवं अन्य संदिग्ध कानाजात बरामद किया गया है। एसडीपीओ वन अजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक साइबर फ्राड स्कार्पियो से जा रहा है, उसके पास प्राउट करने के सामान भी है। सूचना पर तत्काल पहल करते हुए वाहन चेकिंग चलाया गया। वाहन चेकिंग के कम में ही एक काले रंग के स्कार्पियों को छापामारी दल की उपस्थित पुलिस पदाधिकारी ने पकड़ा। वाहन एवं उसके चालक अजीत कुमार मेनर के खासपुर निवासी हैं। विधिवत तालासी लेने पर साईबर फ्राड से संबंधित आवश्यक सामान बरामद हुआ। पृष्ठताछ में अजीत ने अपने साथियों के नाम उजागर किया है।ब्यामद सामानों में एक स्कार्पियो वाहन, 12 मोबाइल,कुल-11 एटीएमकार्ड,13 पैन कार्ड,3 आधार कार्ड,एक ड्राईवरी लाइसेंस,एक प्रेस कार्ड,12 नया सीम कार्ड,6 काजज पुडिया में लपेटा हुआ 10 सीम,शतीन मोहर स्टॉम,बैंक पासबुक-एक एवं चेक बुक 02 एवं अन्य सामान बरामद किया गया।



संक्षिप्त खबरें

जलजमाव से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, समाधान की उड़ाई मांग

मधुबनी। कलूआही प्रखंड की मलमल दक्षिण पंचायत के वार्ड 12 व 13 में जलजमाव और जल निकासी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने गुरुवार को सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बरसात के दौरान सड़क और गलियों में पानी भर जाने से लोगों का आवागमन बाधित हो जाता है तथा स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नालों की सफाई और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने जाम नालों की सफाई, खुले नालों पर ढक्कन लगाने और नियमित रखरखाव की मांग करते हुए चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। पंचायत प्रशासन की ओर से इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पूर्व मेयर सलीर कुमार हत्याकांड: कोर्ट ने सत्यों के अभाव में सभी 6 आरोपियों को किया बरी

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार की हत्या के मामले में पहले सेशन ट्रायल का बहुप्रतीक्षित फैसला गुरुवार को आ गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में मामले के सभी छह आरोपियों—श्याम नंदन मिश्रा, सुशील कुमार छापड़िया, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिटू सिंह, नवीन कुमार, सुजीत कुमार और कुमार रंजय ओंकार—को बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने अभियोजन पक्ष और पुलिस की जांच पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ऐसे ठोस सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिनके आधार पर आरोप सिद्ध किए जा सकें। पर्याप्त एवं पुष्टा प्रमाण नहीं होने के कारण अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह मामला 23 सितंबर 2018 का है, जब चंदवारा नवाम रोड के पास अपराधियों ने पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थीं। इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे मुजफ्फरपुर में सनसनी फैल गई थी और मामले ने राज्यभर का ध्यान अपनी ओर खींचा था। जांच के दौरान इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुछ आरोपियों की पहले ही हत्या हो चुकी है।

अखंड सुहाग की रक्षा के लिए 3 अगस्त से शुरूहुआ मधुश्रावणी व्रत

मनौगाछी (दरभंगा)। विवाह के प्रथम वर्ष के श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से आरंभ करके श्रावण शुक्ल तृतीया को संपन्न होने वाले इस व्रत का मिथिलांचल के महिलाओं में विशिष्ट महत्व है। प्राचीन काल से चले आ रहे इस विशेष व्रत को नव विवाहिताओं द्वारा बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक मनाने की परंपरा है नव विवाहिताएँ एक पखवाड़ की अवधि में नियम पूर्वक आहार का सेवन करते हुए राग,गौरी एवं विवहारा की पूजा नियमित रूप से करती हुई इनकी पौराणिक कथाओं का श्रवण करती हैं। मिथिलांचल की परंपराओं में नव विवाहिताएँ सामूहिक रूप से देव मंदिरों के परिसरों तथा फूलों के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों का चयन करती हैं और मिथिला के परंपरिक गीतों का गायन करती हुई घर को लौटती हैं ऐसी मान्यता है कि इस पूजा में वासी फूलों से पूजा अर्चना करने से फल मिलते हैं नव विवाहिताएँ इस अवधि में अपनी सहेली के वस्त्र एवं वहां से आए भोज्य पदार्थों का ही सेवन करती हैं इस अवधि में भोजन में सैंधव प्रयोग के अतिरिक्त सामान्य नमक का प्रयोग निषिद्ध माना गया है नाग पंचमी के दिन से आरंभ होने वाले इस विशेष व्रत के संबंध में ऐसी मान्यता है कि नाग की पूजा से महिलाओं में वैधव्य योग नहीं होता है।

हल्की बारिश से तापमान में आई गिरावट , मौसम हुआ सुहावा

मुजफ्फरपुर। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा स्थित जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र द्वारा जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को क्षेत्र में मौसम अपेक्षाकृत सुहावा रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान 28.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। सुबह 7 बजे सापेक्ष आर्द्रता 95 प्रतिशत तथा दोपहर 2 बजे 81 प्रतिशत दर्ज की गई।

अहिल्या गौतम स्थान मंदिर के जीर्णोद्धार व विकास कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण

●निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सभी कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश

प्रातः किरण संवाददाता

दरभंगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आज जिले के अहियारी गांव स्थित अहिल्या गौतम स्थान मंदिर परिसर का निरीक्षण कर वहां चल रहे जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में संचालित जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य,पोखर के सौंदर्यीकरण, चाररदीवारी निर्माण सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अभियंताओं से कार्यों की वर्तमान स्थिति, प्रगति एवं शेष कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग एवं कार्यपालक अभियंता पर्यटन विभाग



को सभी निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने धर्मशाला के जीर्णोद्धार कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि धर्मशाला का

जीर्णोद्धार इस प्रकार किया जाए जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध हो सके जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग एवं कार्यपालक अभियंता,पर्यटन विभाग को निर्देश दिया कि सभी निर्माण एवं विकास कार्यों की नियमित

संविदा सफाई कर्मियों ने राज्यव्यापी हड़ताल के समर्थन में निकाला मार्च, नियमितीकरण सहित कई मांगे उठाई

प्रातः किरण संवाददाता

मधुबनी। जयनगर राज्यभर में संविदा एवं आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सफाई कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में गुरुवार को नगर पंचायत जयनगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के बैनर तले समर्थन मार्च निकाला गया। इसके बाद आयोजित सभा में सफाई कर्मियों ने नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा बकाया वेतन के भुगतान की मांग उठाई। कार्यक्रम का नेतृत्व यूनियन के सचिव शोभीत मंडल एवं अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने किया। इस दौरान यूनियन के संरक्षक एवं ऐक्ट्व नेता भूषण सिंह भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को स्थायी किया जाए तथा ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर सम्मानजनक



एवं सुरक्षित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी कर्मियों को पीएफ, ईएसआई, चिकित्सा सुविधा, बीमा, पेंशन सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ देने और बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई। सभा को संबोधित करते हुए शोभीत मंडल ने कहा कि सफाई कर्मी नगरो को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन, सुरक्षा उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो रही हैं। अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने वषों से कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण

मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के कायाकल्प को मिली रफ्तार, विधायक ईश्वर मंडल ने किया निरीक्षण

प्रातः किरण संवाददाता

दरभंगा। दरभंगा ग्रामीण विधायक सह जदयू जिलाध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ ईश्वर मंडल की पहल पर कबराघाट स्थित मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के व्यापक विकास कार्यों में तेजी आई है। करोड़ों रुपये की लागत से प्रस्तावित नए भवन, बाउंड्री वॉल, सौंदर्यीकरण एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गुरुवार को विधायक ने संस्थान परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ईश्वर मंडल ने कहा कि मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं वैदिक परंपरा को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध एवं अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना



को साकार करने में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा की दूरदर्शी सोच और विशेष पहल महत्वपूर्ण रही है।उन्होंने बताया कि श्री झा के प्रयासों से हाल ही में मिथिला संस्कृत शोध संस्थान और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के बीच संस्थागत सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। विधायक

ने कहा कि यह सहयोग मिथिला की प्राचीन ज्ञान-परंपरा, संस्कृत साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। विधायक ने विश्वास जताया कि संस्थान के आधुनिक स्वरूप में विकसित होने से शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं संस्कृत विद्वानों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मिथिला की बौद्धिक विरासत को नई ऊर्जा मिलेगी।

10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प

विभूतिपुर/समस्तीपुर।

प्रखंड के वासीटोल स्थित एक निजी संस्थान में डीवाईएफआई, एडवा, सीटू, खेत मजदूर यूनियन और किसान सभा की एक संयुक्त बैठक हुई।अध्यक्षता श्याम किशोर कमल ने की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त को होने वाले राष्ट्रव्यापी ह्राजेल भरो आंदोलनहू के तहत विभूतिपुर के सभी कार्यकर्ता समस्तीपुर समाहरणालय पहुंचकर बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देशें ाैठक को संबोधित करते हुए विभूतिपुर विधायक सह किसान सभा के राज्य अध्यक्ष अजय कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को मजदूर-किसान विरोधी बताया। उन्होंने इस आंदोलन को निर्णायक बताया। इसके अलावा रामाश्रय महतो, बबलू कुमार, सिया प्रसाद यादव, क्रांति कुमार और दिलीप पॉजियार समेत कई नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। बैठक में जागेश्वर महतो, लूटन राय, ललन सुभान, राम ज्ञान महतो, कैलाश पासवान, शंकर शर्मा, देवेन्द्र सिंह, बंधु महतो, जगदीश महतो, राम पुनीत शर्मा, विष्णु देव प्रसाद सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कृष्णमूर्ति, रामचंद्र महतो, छोटन साहनी सहित दर्जनों स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित थे।



मटके कछुए का सुरक्षित रेस्क्यू, जीवछ नदी में किया गया पुनर्स्थापन

मधुबनी। वरीय उपसमाहर्ता की तत्परता और संवेदनशीलता से ऑफिसर्स कॉलोनी में भटके एक कछुए का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास जीवछ नदी में पुनर्स्थापित किया गया। यह पहल जलीय जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय उदाहरण बनी ज्ञानकारी के अनुसार, देर रात वरीय उपसमाहर्ता के सरकारी आवास के समीप एक कछुआ विचरण करता हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने कछुए की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसे सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थान पर रखा और तत्काल वन परिसर पदाधिकारी



कछुआ स्वाभाविक रूप से अपने प्राकृतिक वातावरण की ओर बढ़ गया। वन अधिकारियों ने बताया कि कछुए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और जल स्रोतों की स्वच्छता तथा जैव विविधता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्र में दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने या स्वयं पकड़ने अपने संरक्षण में लेकर आवश्यक देखभाल की जाए। अगले दिन विभागीय मानकों के अनुरूप डीपीओ नामागि गंगे आनंद अंकित की उपस्थिति में कछुए को जीवछ नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। नदी में छोड़े जाने के बाद

पति की निर्मम हत्या के जूर्म में पत्नी व कथित प्रेमी को आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार अर्थयदंड

दरभंगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदिदेव के अदालत ने प्रेम प्रसंग में पति की निर्मम हत्या के जूर्म में सिमरी थानाक्षेत्र के कमरौली कीसमी संगीता देवी और उससे कथित प्रेमी कुन्दन कुमार उर्फ बजरंगी को आजीव सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थथदंड की सजा सुनाई है। अर्थथदंड नही चुकाने पर दोनो जूर्मियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सिमरी थाना कांड संख्या 147/23 से जुड़े सत्रवाद संख्या 675/23 की सुनवाई पुरी कर अदालत नेगत 24 जुलाई को ही कमरौली निवासी रामाशीष साह के 40 वर्षीय पुत्र राम कुमार साह की निर्मम हत्या की जूर्म में मृतक की पत्नी संगीता देवी धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया था। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी दिलीप कुमार साह ने बताया कि गुरुवार को अदालत में दोनों जूर्मियों का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष का वहरश सूरने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद सजा सुनाई है।यह घटना 21 जुलाई 2023 की रात सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव स्थित कुमरपट्टी चौर में एक मुर्गी फार्म पर हुई थी। मामले की प्राथमिकी मृतक के पिता रामाशीष साह ने दर्ज कराई थी।एपीपी श्री साह ने बताया कि घटना के दिन राम कुमार साह के बच्चे का जन्मदिन था। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए वह अपनी पत्नी के पास मुर्गी फार्म पहुंचा था। आरोप है कि उसकी पत्नी संगीता देवी पांच बच्चों की मां है जिसका कुंदन दास से प्रेम प्रसंग था और वह अक्सर उसके मुर्गी फार्म पर रहती थी।घटना की रात करीब 1१ बजे मृतक के पिता को सूचना मिली कि उसके पुत्र को मुर्गी फार्म पर मार रहा है।उसके पिता रामाशीष साह और स्वजन वहां पहुंचे तो देखा कि राम कुमार को दोनों आरोपित लाठी-डंडे से पीट रहे थे। आरोप है कि बर्बरतापूर्वक मृतक का आंख भी जूर्मियों ने फोर डाली थी। गंभीर चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

हिंदी विभाग के उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन, कक्षा में उपस्थिति और विभागीय गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। प्राचार्य डॉ. शंशु कुमार यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन, नैतिक मूल्यों तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अपनाने की प्रेरणा दी और हिंदी विभाग द्वारा आयोजित गरिमामय कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम में डॉ. सुप्रीत शालिनी, डॉ. संगीता कुमार सहित विभाग के शिक्षक एवं चार दर्जन से अधिक छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। संचालन डॉ. ज्वाला चंद्र चौधरी ने किया। अंत में अतिथियों ने नवागंतुक विद्यार्थियों को कलम एवं मिठाई भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया।



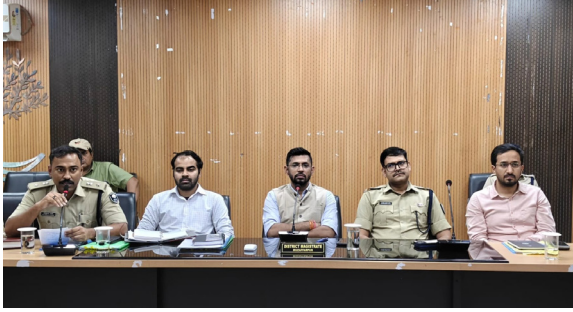
मुजफ्फरपुर

जिलाधिकारी ने की श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा

पदाधिकारियों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुदृढ़ एवं त्रुटिहीन तैयारी सुनिश्चित का दिया निदेश

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने कहा है कि श्रावणी मेला का आयोजन पूर्णतः सुविधापूर्ण एवं दुर्घटना मुक्त होना चाहिए। उल्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुदृढ़ सुरक्षा-व्यवस्था एवं सुचारु यातायात-प्रबंधन के लिए सभी पदाधिकारी सजग, सक्रिय एवं तत्पर रहें। वे बुधवार को मेला के आयोजन हेतु समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित एक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि मेला का सफल आयोजन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। द्वितीय एवं तृतीय सोमवार को काफी भीड़ रहती है। अतः भीड़ नियंत्रण के मानको का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही



बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने कर्तव्य स्थलों पर मुस्तैद रहें एवं सजग तथा सक्रिय होकर कार्य करें। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसका अनुश्रवण करें। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की स्पॉट

बीफिंग भी करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए हर प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए। नियंत्रण कक्ष, वॉच टावर, ड्रॉप गेट, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग, बिजली, साफ-सफाई, चिकित्सा शिविर, ट्रैफिक व्यवस्था, एसडीआरएफ, पेयजल,शौचालय

सुविधा सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि उन्नत एवं सुविकसित कॉम्युनिकेशन प्लान के साथ सभी पदाधिकारी मुस्तैद रहें। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर से सरैयागंज टावर तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जन सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। श्रद्धालुओं का मार्ग पूरी तरह अवरोध-मुक्त रहना चाहिए। ट्रैफिक प्लान का अक्षरशः अनुपालन करें। पार्किंग स्थल से इतर गाड़ी नहीं रहनी चाहिए। श्रद्धालुओं के रास्ते में कोई भी अनधिकृत वेण्डर या दुकान नहीं रहना चाहिए। सड़क अल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी जिम्मेदारी

निर्धारित कर अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने बैरिकेडिंग, साफ सफाई की व्यवस्था, सड़क का सुदृढ़ीकरण, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग की व्यवस्था, विद्युत एवं प्रकाश की व्यवस्था, ठहराव स्थल की व्यवस्था, पेयजल,शौचालय की व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन, भीड़ प्रबंधन, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, विधि-व्यवस्था संधारण, साइनेज एवं अन्य बिन्दुओं पर एक-एक कर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों से भी विस्तृत विमर्श किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को फुकुली मोड़ से बाबा गरीब नाथ मंदिर तक श्रद्धालुओं के आने-जाने वाले पूरे मार्ग एवं स्थलों को अवरोधमुक्त एवं सुविधायुक्त बनाने का निर्देश दिया।

विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार, दोवाडों में सड़क व नाला निर्माण का शिलान्यास

मुजफ्फरपुर।। कांटी नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने की दिशा में विधायक सह पूर्व मंत्री ई. अजीत कुमार ने वाई संख्या 15 में सड़क एवं नाला निर्माण तथा वाई संख्या 24 में नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांटी नगर परिषद निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बरसात समाप्त होने के बाद विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी। शिलान्यास के बाद विधायक ने स्थानीय लोगों से निर्माण कार्यों की निगरानी करने की अपील करते हुए कहा कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे होने चाहिए। उन्होंने संवेदक को निर्देश दिया कि निर्माणधीन नालियों को मुख्य नाली से जोड़ा जाए, ताकि बरसात और अन्य मौसम में जलजमाव की समस्या उत्पन्न न हो और लोगों को राहत मिल सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक ई. अजीत कुमार का भव्य स्वागत किया तथा क्षेत्र में विकास कार्य शुरू कराने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति दिलीप कुमार, उपसभापति अयुक्त कुमार गुप्ता, पार्षद पूनम गुप्ता, संजय साह, संतोष पासवान, रामकुमार मोनु, राममोहन पासवान, पार्षद प्रतिनिधि शंकर प्रसाद, जितेंद्र यादव, रामनाथ गुप्ता, सुमन कुमार सिंह, पवन कुमार, नौरज मिश्रा, रमेश ठाकुर, श्याम किशोर मिश्रा, प्रभु गुप्ता, नंदन महतो सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

शहर में दिनदहाड़े फ्लैट के बाहर से नई हॉंडा शाइन बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध

मुजफ्फरपुर। शहर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं के बीच गुरुवार को मझौलिया इलाके में दिनदहाड़े एक नई होंडा शाइन मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने सदर थाना में अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, अन्य कुमार के नाम से मुजफ्फरपुर परिवहन कार्यालय में पंजीकृत नई होंडा शाइन मोटरसाइकिल सुबह करीब 10 बजे मझौलिया स्थित उनके फ्लैट के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बाइक लेकर फरार हो गया। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है।

मिसेज बिहार 2026 बनीं मुजफ्फरपुर की बहू, स्कूल पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। प्रतिष्ठित ह्यमिसेज बिहार 2026 का खिताब जीतने के बाद मुजफ्फरपुर की बहू एवं शांति निकेतन आवासीय विद्यालय की डायरेक्टर सोनी गुप्ता का पहली बार विद्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। स्कूल परिसर में प्रिंसिपल, शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका अभिनंदन किया तथा उनकी उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। पटना के एक होटल में आयोजित विवाश्री मिसेज बिहार 2026 प्रतियोगिता में कड़े मुकाबले के बाद सोनी गुप्ता ने मिसेज बिहार का प्रतिष्ठित ताज अपने नाम किया। विजेता बनने पर उन्हें आकर्षक क्राउन के साथ 50 हजार



रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। सोनी गुप्ता की सफलता इसलिए भी प्रेरणादायक मानी जा रही है क्योंकि वह तीन बच्चों की मां हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ, वह शांति निकेतन आवासीय विद्यालय की डायरेक्टर के रूप में भी अपनी

जिम्मेदारियां निभा रही हैं। उनके प्रति पेशे से चिकित्सक हैं। उन्होंने बताया कि परिवार और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने प्रतियोगिता की तैयारी की और अपने पहले ही ब्यूटी पेजेंट में जीत हासिल की। सोनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें इस प्रतियोगिता की जानकारी इंस्टाग्राम के माध्यम से मिली थी। शुरूआत में उनके पति प्रतियोगिता में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने सपनों के बीच संतुलन बनाकर अपने परिवार के सामने रखा। इसके बाद उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिला। प्रतियोगिता से पहले उन्होंने 15 दिनों के विशेष श्रुमिंग सेशन किया, जिसमें व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास, प्रस्रिषण कौशल और स्ट्रेज प्रेजेंस का प्रशिक्षण दिया गया। इसी तैयारी

नगर आयुक्त,सिटीएसपीसमेत अधिकारियों ने श्रावणी मेला रूट का किया निरीक्षण

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। श्रावणी मेला की दूसरी सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह सक्रिय हो गया है। गुरुवार को नगर आयुक्त, सिटी एसपी, ट्रैफिक डीएसपी, नगर डीएसपी, नगर निगम के अधिकारियों तथा भवन विभाग के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से श्रावणी मेला रूट का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्देश दिया कि दूसरी सोमवारी पर आने वाले कार्रवियों को किसी प्रकार की अवधिा नहीं होनी चाहिए। पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, चिकित्सा सहायता और यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने कहा कि कार्रवियों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग स्थलों की स्पष्ट व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग स्थल, कांवरिया मार्ग, विश्राम स्थल तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। प्रशासन का लक्ष्य है कि दूसरी सोमवारी के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।

प्रोफेसर के आकस्मिक निधन पर संत प्रेम भिक्षु इंटर कॉलेज में शोक

मुजफ्फरपुर। संत प्रेम भिक्षु इंटर कॉलेज के मैथिली विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ शिक्षक प्रोफ़ेसर अवधेश कुमार सिंह का 6 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे हृदिराट में हृदयाघात के कारण आकस्मिक निधन हो गया। प्रो. अवधेश कुमार सिंह के निधन की खबर से कॉलेज प्रबंधन एवं शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वे एक समर्थक, अनुशासित एवं विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय शिक्षक थे। उनके निधन को शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कॉलेज के शिक्षकों ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।समाजशास्त्र के प्रोफ़ेसर सोनू सरकार ने कहा कि प्रोफ़ेसर अवधेश कुमार सिंह का आकस्मिक निधन हम सभी के लिए अलंनं पीड़ादायक और अपूरणीय क्षति है। वे केवल एक अच्छे शिक्षक ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के प्रति सदैव संवेदनशील रहने वाले, सरल एवं सहज व्यक्तित्व के धनी थे। अपने विषय पर अपनी गहनवृत्त पकड़ और पढ़ाने की विनोदशैली के कारण वे विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय थे। सहकर्मियों के साथ भी उनका व्यवहार हमेशा आत्मीय और सहयोगपूर्ण रहा। उनके निधन से हमने एक अनुभवी शिक्षक, अच्छे सहकर्मी और एक संवेदनशील इंसान को खो दिया है। उनकी कमी लंबे समय तक महसूस होती रहेगी।

राष्ट्रीय दैनिक प्रातःकिरण 05 पटना, शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026

डीएम ने मांगा राजस्व कर्मचारियों के योगदान का प्रतिवेदन

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कुल 200 राजस्व कर्मचारियों को अन्य जिलों से मुजफ्फरपुर जिला में स्थानांतरित किया गया था। उक्त आलोक में जिलाधिकारी द्वारा इन अंतर-जिला स्थानांतरित राजस्व कर्मचारियों को

कंप्यूटर-आधारित रैंडमाइजेशन विधि द्वारा मुजफ्फरपुर के 16 अंचलों में पदस्थापित किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को इन नव-पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का योगदान से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। अंचल अधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया है कि इन राजस्व कर्मचारियों

को हल्का आवंटित करते हुए राजस्व संबंधी कार्यों का समयमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन को उत्तरदायी, अनुशासित एवं जनोन्मुख बनाना है। पारदर्शी एवं तकनीक-आधारित स्थानांतरण तथा पदस्थानन व्यवस्था से इस प्रयास को और बल मिलेगा।

पुतुल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, फरार नामजद आरोपी धीरज कुमार गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के पताही मोहम्मदपुर गांव में चंचित टेंट हाउस संचालक पुतुल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे नामजद आरोपी धीरज कुमार को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से सदर थाना में गहन पूछताछ की जा रही है।सदर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार ने बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं मामले में फरार अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में धीरज कुमार के पिता विजय बैठा को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शोध परिषद की दोदिवसीय बैठक प्रारंभ

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के विद्यापति सभागार में गुरुवार को 21वीं शोध परिषद , खुरीफ-2026 (विशेष) को दो दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। बैठक का उद्देश्य विश्वविद्यालय निधि से वित्त पोषित 62 नई शोध परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें अनुमोदित करना था। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी. एस. पाण्डेय ने कहा कि देश में कृषि का परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है । आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एग्रीकल्चर और रोबोटिक्स पुरी दुनिया के कृषि के स्वरूप को बदल देंगे। इसलिए जरूरी है कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अभी से इन क्षेत्रों में शोध करने देश की कृषि को बढ़ावा दे और इसे विश्व में सबसे उन्नत बनायें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 तक देश को विकसित करने में कृषि वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुसंधान परिषद की इस विशेष बैठक में इन सब क्षेत्रों के अतिरिक्त कृषि से संबद्ध अन्य क्षेत्रों में शोध की परियोजना की प्रस्तुति होगी और उनकी गहन समीक्षा के बाद स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नवसारी एह जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. ए.



आर. पाठक, ने कहा कि विश्वविद्यालय न देश भर में डिजिटल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि एनआइआरएफ रैंकिंग में विश्वविद्यालय ने तीन वर्षों में 52 वें रैंक से आठवां रैंक हासिल किया है, यह विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास को दिखाता है। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय ने रोबोटिक्स और प्रेसिजन एग्रीकल्चर में जो अनुसंधान शुरू किया है उसके परिणाम से देश की प्रतिय्धा में भी वृद्धि होगी। कोटा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. ए. के. व्यास ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने संसाधनों से एक सौ से अधिक शोध परियोजनायें चला रहा है और इस विशेष बैठक में 62 नये शोध परियोजनाओं को स्वीकृति के उपरांत विश्वविद्यालय के संसाधनों से वित्त पोषित किया जायेगा। यह अपने आप में एक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि डिजिटल और डेटा आधारित कृषि समाधान किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होंगे निदेशक शोध डॉ. ए. के. सिंह ने स्वागत भाषण में कहा

सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के संचालन समय में आंशिक संशोधन करते हुए शनिवार को सभी सरकारी विद्यालयों में हाफ डे लागू करने का आदेश जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सोमवार से शुक्रवार तक विद्यालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक, जबकि शनिवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक संचालित होंगे। आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शनिवार को पूर्व निर्धारित गतिविधियां निर्धारित समय के भीतर संचालित की जाएंगी। दोपहर 12:00 बजे तक कक्षाएं एवं अन्य गतिविधियां चलेंगी। इसके बाद 12:00 बजे से 12:40 बजे तक मध्याह्न भोजन कराया जाएगा और भोजन के उपरांत विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी जाएगी। वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार को दोपहर 1:00 बजे तक अध्ययन एवं अन्य निर्धारित गतिविधियां संचालित होंगी, जिसके बाद छात्र-छात्राओं को अवकाश दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रतिदिन एक घंटे तक पाठ्य योजना तैयार करने, मूल्यांकन कार्य, शिक्षक डायरी अद्यतन करने, गृहकार्यों की जांच, प्रयोगशाला प्रबंधन तथा आवश्यकतानुसार रिमिडियल कक्षाएं संचालित करेंगे। इन कार्यों के पूरा होने के बाद ही विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। विभागीय आदेश में कहा गया है कि अन्य सभी पूर्व निर्धारित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

बालिदान दिवस पर मुजफ्फरपुर पहुंचेगा सिद्धेश्वरी काली मंदिर का चरणामुत

प्रात : किरण संवाददाता

मुजफ्फरपुर। भारत की आजादी के अमर बलिदानी खुदीराम बोस की शहरादत को एक सदी से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन फांसी से पहले व्यक्त की गई उनकी एक अपूर्वी इच्छा आज भी लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनी हुई है। कहा जाता है कि फांसी से पूर्व खुदीराम बोस अपने पैतृक गांव मदिनापुर स्थित सिद्धेश्वरी काली मां का पवित्र चरणामृत ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इसी अधूरे संकल्प को प्रतीकात्मक रूप से पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से पश्चिम बंगाल के मदिनापुर के लोग हर

प्रेमी जोड़े को पेड़ से बांधकर पिटाई, पंचायत में कराई गई कथित शादी

प्रात : किरण सवाददाता

मुजफ्फरपुर। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने सामाजिक मर्याद और निष्ठा का पंचायत को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मझौलिया पंचायत के वाई संख्या-7 में एक प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों द्वारा पकड़ने, पेड़ से बांधकर कथित रूप से पिटाई करने और पंचायत के बीच शादी कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार, गांव का एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच था। बताया जा रहा है कि युवक पहले से विवाहित है। अपने दौरान स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़ लिया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि भीड़ ने कानून अपने हाथ में लेते हुए दोनों को पेड़ से बांध दिया और उनके साथ मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,

भीड़ के सामने दोनों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया और कई लोग पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते रहे। इसके बाद पंचायत के कथित निर्णय के आधार पर युवती की शादी उसी विवाहित युवक से करा दी गई। इस घटना ने समाजिक और कानूनी दोनों स्तरों पर बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि युवक पहले से शादीशुदा था, तो उसकी दूसरी शादी किस आधार पर कराई गई। कानूनी जानकारों का कहना है कि किसी भी विवाद का समाधान भीड़ या पंचायत के दबाव में नहीं, बल्कि विधिसम्मत कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। किसी व्यक्ति को बंधक बनाना, मारपीट करना या जबरन कोई फैसला लागू करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। सकरा थाना पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञा लेते हुए जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध था और ग्रामीणों को आशंका थी कि दोनों घर छोड़कर भागने की तैयारी में थे।



उच्च शिक्षा परिसरों में एचआईवी के बढ़ते मामले: अब चुप्पी नहीं, संवाद जरूरी

डॉ. सत्यवान सौरभ

देश का भविष्य उसके युवा तय करते हैं और युवा शक्ति का सबसे बड़ा केन्द्र हमारा विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं। ऐसे में यदि किसी राज्य से यह समाचार सामने आए कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी एचआईवी (लकड़) संक्रमण से प्रभावित पाए गए हैं और सरकार को उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यापक जांच अभियान चलाने का निर्णय लेना पड़ा है, तो यह केवल स्वास्थ्य विभाग का विषय नहीं रह जाता। यह शिक्षा, समाज, परिवार, नीति-निर्माताओं और पूरे राष्ट्र के लिए गंभीर चेतावनी है। यह समय भय फैलाने का नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और व्यापक जागरूकता के साथ इस चुनौती का सामना करना है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंस वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। यह समय पर जांच और उपचार न मिले तो यह एड्स (अच्छर) किसी गंभीर अस्थायी तक पहुँच सकता है। हालाँकि चिकित्सा विज्ञान की प्रगति ने इसे अब एक नियंत्रित बीमारी बना दिया है एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (अच्छर) की सहायता से संक्रमित व्यक्ति सामान्य और लंबा जीवन जी सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है समय पर पहचान, नियमित उपचार और संक्रमण को रोकथाम। युवाओं में एचआईवी संक्रमण की खबर कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। क्या हमारे शैक्षणिक संस्थानों में स्वास्थ्य और यौन शिक्षा पर्याप्त है? क्या युवाओं को सुरक्षित व्यवहार, संक्रमण के कारणों और बचाव के उपायों की वैज्ञानिक जानकारी मिल रही है? क्या परिवार और समाज इस विषय पर खुलकर संवाद करने को तैयार हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि समाज केवल स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक सोच और शिक्षा व्यवस्था की भी है। भारतीय समाज में आज भी यौन स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना सहज नहीं माना जाता। माता-पिता संकोच करते हैं, शिक्षक कई बार इस विषय से बचते हैं और विद्यार्थी अधूरी या भ्रामक जानकारी इंटरनेट अथवा मित्रों से प्राप्त करते हैं। परिणामस्वरूप मिथक, भ्रांतियाँ और गलत नियम जन्म लेते हैं। जबकि वैज्ञानिक जानकारी ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह समझना भी आवश्यक है कि एचआईवी संक्रमण केवल असुरक्षित यौन संबंधों से ही नहीं, बल्कि संक्रमित रक्त चढ़ाने, संक्रमित सुई के प्रयोग तथा संक्रमित माँ से शिशु तक भी फैल सकता है। वहीं हाथ मिलाने, साथ बैठने, भोजन साझा करने, गैले लीने, छींकने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता। दुर्भाग्य से आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग इन तथ्यों से अनभिज्ञ है। यही अज्ञानता संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को जन्म देती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अथयन्त्रन युवा जीवन के ऐसे दौर में होते हैं जहाँ स्वतंत्रता, जिज्ञासा और नए अनुभवों का विस्तार होता है। ऐसे में उन्हें सही दिशा देना केवल परिवार का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों और सरकार की भी जिम्मेदारी है। प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य परामर्श केंद्र, प्रशिक्षित काउंसलर, गोपनीय जांच सुविधा और निर्यात जागरूकता कार्यक्रम चालिए। विद्यार्थियों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि यदि वे किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ आगे आते हैं, तो उनकी निजता और सम्मान पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यदि किसी राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों में एचआईवी जांच अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, तो इसका उद्देश्य केवल संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करना नहीं होना चाहिए। इसके साथ परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, उपचार और जागरूकता को समान महत्व देना होगा। जांच तभी सफल होगी जब विद्यार्थी इसे भय या शर्म के बजाय स्वास्थ्य सुरक्षा का सामान्य कदम मानें। मीडिया की भूमिका भी यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी आंकड़े या घटना को सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करने से समाज में भय और भ्रम पैदा होता है। इसके विपरीत यदि मीडिया वैज्ञानिक तथ्यों, विशेषज्ञों की राय और जागरूकता पर आधारित संवाद को बढ़ावा दे, तो समाज अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बन सकता है। बीमारी को अपराध या चरित्र से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति को समाप्त करना भी आवश्यक है। आज नशी की बढ़ती प्रवृत्ति भी चिंता का विषय है।

मुआवजे में उलझ कर रह गई विकास की राह

अंकि कुमारी

गांव तक सड़क पहुंचना केवल विकास की एक परियोजना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षित आवागमन तक पहुंचना का संकेत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य भी ग्रामीण परिवारों को हर मसौम में चलने योग्य सड़कों से जोड़ना है। बिहार में इस दिशा में लंबे समय से काम हुआ है और बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिहार में इसके तहत 52,095.37 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका था, जबकि 3,439.10 किलोमीटर सड़क निर्माणधीन थी। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में ग्रामीण सड़कों का निर्माण पर्याप्त है, जो ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बना रहा है। राज्य के कुल गांवों में जहां आज भी पक्की सड़क गांव के भीतर तक नहीं पहुंच सकी है। इसके पीछे हर बार प्रशासनिक उदासीनता या अन्याय का कमी ही ज़िम्मेदार हो, यह जरूरी नहीं। कई बार विकास और निर्माण के अभाव में ग्रामीणों के अधिकार के बीच पैदा हुआ विवाद भी सड़क को रोक देता है। सीतामढ़ी के ललितपुर गांव की स्थिति इसी जटिलता की ओर इशारा करती है। इस गांव के अंदर पक्की सड़क पहुंचाने की राह में कुछ लोगों की निजी जमीन आ रही है। सरकार की ओर से जमीन के बदले मुआवजा देने की व्यवस्था है, लेकिन जमीन मालिकों का कहना है कि उन्हें मिलने वाला मुआवजा जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य की तुलना में कम है। इसी असहमति के कारण ये सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। पक्की सड़क न होने का सबसे बड़ा असर बाजार के दिनों में दिखाई देता है। कच्चे रास्ते पर पानी और कोहर जमा होने के बाद पैदल चलना भी कठिन हो जाता है। ऐसे समय में ग्रामीणों को दूसरी गाड़ियों का गांव के अंदर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बीमारी या प्रसव जैसी आपात स्थिति में यह समस्या परिवार के लिए खतरा हो सकती है। सड़क की कमी का असर केवल मरीजों के परिवार तक सीमित नहीं रहता। परिवार के किसी सदस्य को उसे मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय और श्रम लगाना पड़ सकता है। इस सड़क की समस्या का एक और कम दिखाई देने वाला असर शिक्षा पर पड़ता है। गांव की किशोरियों के लिए स्कूल तक पहुंचना केवल दूरी का मामला नहीं है। रास्ते की स्थिति, मौसम, परिवहन की उपलब्धता और परिवार की सुरक्षा संबंधी चीजें भी उनकी नियमित पढ़ाई को प्रभावित करती हैं। जब रास्ता खराब होता है तो स्कूल जाने और स्कूल में अधिक समय लगता है। बारिश में कीचड़ और जलभराव के कारण अकेले निकलना कठिन हो जाता है। परिवार कई बार किशोरियों को ऐसे रास्ते से भेजने में हिचकिचाता है, खासकर तब जब स्कूल गांव से बाहर हो। नतीजा यह हो सकता है कि कुछ दिनों की अनुपस्थिति के कारण धीरे-धीरे पढ़ाई से दूरी में बढ़ल जाए। यह समस्या इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण किशोरियों के लिए शिक्षा का हर अतिरिक्त दिन उनके भविष्य के विकल्पों को बढ़ाता है। स्कूल तक पहुंचने में कठिनाई केवल आज की परेशानी नहीं है। इसका संबंध आगे की पढ़ाई, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी से भी है। यह है, तो उसके अवसर भी सीमित हो सकते हैं। दूसरी ओर गांव में बेहतर सड़क होने पर स्कूल, बाजार, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक परिवहन सहज आसान हो जाता है। इससे परिवारों को भी किशोरियों की शिक्षा जारी रखने का अधिक भरोसा मिलता है।

यूजीसी नियमों का विवाद, करणी सेना का आंदोलन और राजस्थान की चुनावी राजनीति

आयोग का तर्क था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से मौजूद व्यवस्था को अधिक प्रभावी और कठोर बनाया जाना आवश्यक है। इसी सोच के साथ नए नियम अधिसूचित किए गए। हालांकि इन नियमों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद कई पक्षों ने इन्हें चुनौती दी और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतिम रोक लगा दी। वर्तमान में विद्वेष्टावादी और कॉलेजों में वर्ष 2012 के पुराने नियम ही लागू हैं। इसके बावजूद करणी सेना और अन्य सर्वांग संगठनों का कहना है कि केवल न्यायालय की अंतिम रोक पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क है कि यदि भविष्य में न्यायालय यह रोक हटा देता है तो ये नियम स्वतः प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार स्वयं इन नियमों को पूरी तरह वापस ले। विशेष करने वाले संगठनों की मुख्य आपत्ति यह है कि नए नियमों में शिकायत दर्ज होते ही सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना अधिक है और झूठी अथवा दुर्भावपूर्ण शिकायतों से बचाव के पर्याप्त प्राधान्य नहीं किए गए हैं। उनका कहना है कि यदि किसी छात्र पर बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई होती है और उसके प्रवेश, पढ़ाई या भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा।



कांतिलाल मांडोट
(लेखक)

राजस्थान की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहाँ शिक्षा से जुड़ा एक प्रशासनिक और कानूनी मुद्दा अब सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोके के उद्देश्य से अधिभूत नए नियमों के विरोध में श्री रामभूत करणी सेना और अन्य सर्वण संघटना का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। जयपुर में निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस लाठीचार्ज, एक प्रदर्शनकारी की मौत के आरोप और उसके बाद उभरे आक्रोश ने इस विवाद को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब राजस्थान में पंचायतीराज और शहरी शिक्षा चुनाव निकट है। इसलिए इस आंदोलन को केवल एक शैक्षणिक नीति के विरोध तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक प्रभावों पर भी व्यापक चर्चा हो रही है। यूजीसी ने नए नियमों का

उत्तरय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातिजनाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकेना तथा उन्हें प्रोत्थित और समान वातावरण उपलब्ध कराना बनाया था। आयोग का तर्क था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के प्रयास पहले से ही मौजूद व्यवस्था को अधिक प्रभावी और अधिक बनाया जाना आवश्यक है। इसी संसोध के साथ नए नियम अधिसूचित किए गए। हालाकि इन नियमों को अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद कई प्रश्नों ने इन्हें चुनौती दी और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। जनवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाई। वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वर्ष 2012 के पुराने नियम ही लागू हैं। इसके बावजूद करणी सेना और अन्य वर्ण संगठनों का कहना है कि कि केवल न्यायालय की अंतरिम रोक पर्याप्त नहीं है। उनका तर्क है कि यदि भविष्य में न्यायालय यह रोक हटा देता

तो ये नियम स्वतः प्रभावी हो जायेंगे। इसलिये उनकी मांग है कि सरकार स्वयं इन नियमों को पूरी तरह वापस ले। विद्यार्थी करने वाले संगठनों की मुख्य आपत्ति यह है कि नए नियमों में शिकायत दर्ज होते ही सामान्य वर्गों के विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना अधिक है और झूठी अथवा दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से सम्बन्धित के पहला प्राधान्य नहीं किए गए हैं। उनका कहना है यदि किचन स्टाफ पर बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई होती है और उसके प्रवेश, पढ़ाई या भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसकी प्रतिकारभरपाई कोन करेगा। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्राधान्य नहीं है। इसी आधार पर करणी सेना ने इन नियमों की तुलना अर्थीजों के दौर के रोलेट एक्ट से करते हुए कहा कि इसमें आरोपित व्यक्ति को निर्दोष घोषणा अवसर नहीं मिला। दूसरी ओर, इन नियमों के समर्थकों का मानना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में सामाजिक सम्बन्ध से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को सुरक्षित नियामक उपलब्ध कराना राबि

आरंभ और संस्थाओं का जिम्मेदारी है उनका कहना है कि यदि भेदभाव की घटनाओं को रोकेने के लिए सफ़ा न्याय नहीं होगा तो समान अवसर और सामाजिक न्याय का उद्देश्य अपभूत रह जाएगा। इस प्रकार वह विवाद केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक हटकेणों और अधिकारों का अलग-अलग व्याख्याओं का भी विषय बन गया है। जयपुर में करणी सेना द्वारा निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव ने इस पूरे आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकेने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और उसके बाद एक कार्यकर्ता देवरज सिंह पलाड़ा की अस्पताल में मृत्यु को खबर सामने आई। अदालत न्यायिक संगठनों ने इस प्रशासनिक कार्रवाई से जोड़ते हुए सरकार के खिलाफ तीव्र विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद जयपुर में, मुख्यमंत्री आवास के घेराव और राज्यपाला आंदोलन के चेतावनी भी दी गई। इस घटना ने आंदोलन को केवल यूजीसी नियमों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सार्वजनिक प्रति असंतोष के रूप में भी प्रस्तुत किया।

जाने लगा। राजस्थान की राजनीति में समाज समाज, विशेष रूप से राजपूत समुदाय, लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत रूप से इस गण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता रहा है। ऐसे में यदि इस गण में अस्तोते बढ़ता है है तो उसका असर पंचायत और निकाय विधायन पर पड़ सकता है। राजनीतिक विधायकों का मानना है कि स्थानीय चुनावों में सामाजिक समीकरण अधिक प्रभाव होता है और ऐसे पुरे मदादाओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक जानकार इस घटनाक्रम की तुलना पूर्व में आनंदीत एकाडंटर के बाद उभरने पराजित परस्थितियों की एक कर रहे हैं, जब राजपूत समाज के एक हिस्से में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिली थी। उस समय भी यह माना गया था कि यदि समय रहते संधिदाओं और विधायन बाली के प्रयास नहीं किए जायें, तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है। वर्तमान परस्थितियों में भी कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती

मानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ संवाद स्थापित करने की होगी। इस आंदोलन की टाइमिंग भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली में हाल के छत्रम आंदोलनों के बाद अब जुड़ोस की योजनाओं को लेकर राजस्थान में आंदोलन तेज होना कई राजनीतिक संकेत देता है। करणी सेना ने इस मुद्दे को केवल एक संभटनस्थान अभियान नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के अधिकारों और भविष्य से जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि यह अभियान अन्य राज्यों में भी गति पकड़ता है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक विमर्श का विषय बन सकता है। करणी सेना की मांग है कि जुड़ोस को नियमित रूपी तरह वापस लिए जाएं, जातीय उत्पीड़न की शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ भी समान रूप से कठोर कार्रवाई का प्रावधान हो तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के अधिकारों-निर्देश संरक्षण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं।

यूजीसी बिल और बुलडोजर की राजनीति ने बदला क्या बिहार का चुनावी समीकरण ?

कुछ शिक्षाविदों, छात्र संगठनों तथा सामाजिक समूहों ने इसका समर्थन किया तो कुछ ने विरोध भी किया। विरोध करने वाले कुछ वर्गों का मानना था कि प्रस्तावित बदलावों से अवसरों की समानता और प्रतिनिधित्व जैसे मू्यों पर असर पड़ सकता है। इसी दौरान कुछ सर्वांग संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि नीति निर्माण में उनकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। उनका कहना था कि सरकार को सभी वर्गों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए था ताकि किसी भी प्रकार के लेदभाव की भावना पैदा न हो। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल नीति बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसके प्रति लोगों के विश्वास का निर्माण भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। लोकतंत्र में कई बार वास्तविकता से अधिक प्रभाव धारणा का होता है। यदि किसी समुदाय को यह महसूस होने लगे कि उसकी चिंताओं को नहीं सुना जा रहा है, तो वह भावना चुनौती व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल लगातार संवाद, जनसंपर्क और विश्वास निर्माण पर जोर देते हैं। कई बार छोटे-छोटे मुद्दे भी बड़े चुनौती विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं।



जतिन्द्र कुमार सिन्हा
(लेखक)

राजनीति के बला घोषणाओं और नारों से नहीं चलती, बल्कि जनता की धारणा, विचारों और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया की चुनावी परिणामों को गहराई से प्रभावित करती है। किसी भी सरकार का निर्णय यदि समाज के किसी वर्ग में असंतोष या असुरक्षा की भावना पैदा करता है, तो उसका प्रभाव केवल उस वर्ग तक सीमित नहीं रहता बल्कि व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाता है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में दो ऐसे मुद्दे प्रमुखता से चर्चा में रहे हैं। पहला- यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित विधायी बदलावों को लेकर उठी बहस और दूसरा- बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बनने वाली राजनीतिक धारणा। इन दोनों विषयों ने अलग-अलग सामाजिक वर्गों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। एक ओर कुछ स्वर्ण संगठनों और बुद्धिजीवियों ने यूजीसी बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर अपनी आपत्तियां

जाने कराई, वहीं दूसरी ओर बुलडोजर कारवायों की राष्ट्रीय बरस ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच आशंकाओं को जन्म दिया। यूजूसी से जुड़े प्रस्तावित बदलावों पर देशभर में विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई। कुछ शिक्षाविदों, छात्र संगठनों तथा सामाजिक समूहों ने सरकार समर्थन किया तो कुछ ने विरोध भी किया। विरोध करने वाले कुछ वगैरह का मानना था कि प्रस्तावित बदलावों से असरकारी की समानता पर प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर कुछ स्वर्ण संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि नीति निर्माण के अनेक चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। उनका कहना था कि सरकार को सभी वर्गों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए था ताकि किसी भी प्रकार के भेदभाव की भावना पैदा न हो। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल नीति बनाना ही पर्याप्त नहीं

होता है, बल्कि उसके प्रति लोगों के विश्वास का निर्माण भी उसना ही आवश्यक माना जाता है। लोकतन्त्र में कई बार वास्तविकता से अधिक भ्रमभाव धारणा का होता है। यदि किसी समुदाय को यह महसूस होने लगे कि किसी व्यक्ति की चिंताओं को नहीं सुना जा रहा है, तो वह भ्रमनाम चुनावी व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल लगातार संवाद, जनसंपर्क और विश्वास निर्माण पर ध्यान देते हैं। कई बार छोटे-छोटे भ्रमे भी बड़े चुनावी विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में अवैध निर्माणों और अपराध के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय रही है। इन कार्रवाइयों के समर्थकों का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ही आवश्यक है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि ऐसी कार्रवाई हमेशा विधिविधिका प्रक्रिया, न्यायालय के आदेशों

और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण होनी चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार होना चाहिए। इसी वजह से बीच कई राजनीतिक दलों ने बुलडोज़ कार्रवाई को चुनौती मुद्दा भी बनाया। कुछ राजनीतिक विक्षेपकों का मानना है कि जब किसी राज्य में बुलडोज़ कार्रवाई की चर्चा बढ़ती है, तो मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में आशका की भावना उत्पन्न हो सकती है कि ऐसी कार्रवाई उनके विरुद्ध अधिक हो सकती है। दूसरी ओर, इस कारण से भी मुस्लिम मतदाता सहमत नहीं, ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा क्योंकि किसी भी समुदाय के भीतर राजनीतिक मत विविध होते हैं। जिन्हार के संदर्भ में भी कुछ विविधताएँ यह तट रखा कि यदि उत्तर प्रदेश जैसी कठोर कार्रवाई का राजनीतिक संदेश यहां भी जाता है, तो उसका असर मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर पड़ सकता है। हालांकि इस प्रकार के

दावों की पुष्टि व्यापक सर्वेक्षणों और अनुमानित अध्ययनों से ही की जा सकती है। बिहार की राजनीति में अक्सर सरकारी स्तर पर यह कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल की दौरान कानून-व्यवस्था और सामाजिक न्याय संतुलन को लेकर एक अलग राजनीतिक छवि बनाई। उनके समर्थक/वक्ता अक्सर मानते हैं कि विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास उनकी राजनीति की विशेषता रहा है। दूसरी ओर, उनके आलोचक अलग मुद्दे प्रस्तुत कर सवाल उठाते रहे हैं। इसलिए किसी एक समुदाय की भावनाओं को पूर्णतः राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व मानना उचित नहीं होगा। बिहार की राजनीति जातीय और सामाजिक समीकरणों से गहराई से प्रभावित रही है। यहाँ विकास, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कानून-व्यवस्था और स्थानीय नेतृत्व जैसे अनेक मुद्दे मतदान के निर्णय को प्रभावित करते हैं। किसी समय सर्वांग वर्ग के एक हिस्से

में नाराजी दिखाई देती है और दूसरी ओर मुस्लिम मतदाताओं के बीच आशंका का वातावरण बनता है, जो राजनीतिक दल इन दोनों वर्गों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति में किसी भी नीति का मूल्यांकन केवल उसके कार्यान्वयन पहेलुओं से नहीं, बल्कि उसका सामाजिक प्रभाव और जनविविचार से भी किया जाता है। यूजीसी बिना लेखर उक्त सवाल हो या बुलंदोज़ का कार्रवाई को लेखर बनी राजनीतिक बरस, दोनों ने अलग-अलग वर्गों में अलग-अलग प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न की हैं। हालाँकि वह कदम कि किसी एक कारण से पूरे चुनाव परिणाम प्रभावित हो जाए, पर्याप्त प्रमाण के बिना उचित नहीं होगा। चुनाव अनेक कारकों—स्थानीय उम्मीदवार, गठबंधन, विकास कार्य, सामाजिक समीकरण, नेतृत्व और मतदाताओं की प्राथमिकताओं, से मिलकर तय होते हैं।

7 अगस्त : राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

भारत का सांस्कृतिक विरासत
जितनी समृद्ध है, उतनी ही
गौरवशाली उसकी हस्तकला और
हथकरघा परंपरा भी है। भारतीय
हथकरघा केवल वस्त्र निर्माण
की तकनीक नहीं, बल्कि हमारी
सभ्यता, संस्कृति, लोकजीवन
और आत्मनिर्भरता का जीवंत
प्रतीक है। इसी अमूल्य विरासत
के सम्मान और संरक्षण के उद्देश्य
से प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय
हथकरघा दिवस मनाया जाता
है। इस दिवस का विशेष महत्त्व
इसलिए भी है क्योंकि 7 अगस्त
1905 को स्वदेशी आंदोलन का
आरंभ हुआ था। विदेशी वस्त्रों के
बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों का
अपनाने का जो संकल्प उस समय
लिखा गया, वही आज चल रहा

देश की आर्थिक स्वतंत्रता और
आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव
का। इसी ऐतिहासिक स्मृति की
सम्मान देते हुए भारत सरकार
ने वर्ष २०१५ से ७ अगस्त को
राष्ट्रीय हथकरचा दिवस के रूप में
मानने की शुरुआत की। भारतीय
हथकरचा उद्योग हजारों वर्षों से
हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग
रहा है। काशी की बनारसी साढ़ियों,
चंदेरी, महेश्वरी, कांजीवरम,
पटोला, पोचमपल्ली, भागलपुरी
सिल्क और असम का मुगा रेशम
आज विश्वभर में भारतीय शिल्प
कौशल की पहचान हैं। इन वस्तुओं
में केवल धागे नहीं बुने जाते,
बल्कि पढ़ियों का अनुभव,
कलाकारों का श्रम और भारतीय

संस्कृति की आत्मा भी समाहित होती है। हथकरघा उद्योग भारत के सबसे बड़े कुटीर उद्योगों में से एक है। लाखों बुनकर और उनके परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी पर निर्भर हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं के लिए यह उद्योग रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार है। समीप्त संसाधनों में भी हमारे बुनकर अपने कौशल से ऐसे उकृष्ट वस्त्र तैयार करते हैं, जिनकी सुंदरता और गुणवत्ता मशीन निर्मित कपड़ों से अलग पहचान रखती है। आज जब मशीनों से बड़े पैमाने पर वस्त्रों का उत्पादन हो रहा है, तब हमकरघा उद्योग अनेक चुनौतियों का सामना कर

गर्भादिवस

रहा है। बढ़ती लागत, आधुनिक विपणन की कमी, युवाओं का इस व्यवसाय से विमुख होना तथा सस्ते मशीन निर्मात कपड़ों की प्रतिस्पर्धा ने पारंपरिक बुनकरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। यदि समय रहते इन्हें तकनीकी सहयोग, निजामत और उचित मूल्य नहीं मिला, तो अनेक पारंपरिक बुनाई शैलियाँ विलुप्त होने का खतरा झेल सकती हैं।

हथकरघा केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी माध्यम है। हाथ से बने वाले वस्त्रों में ऊर्जा की खपत अपेक्षाकृत कम होती है और उनका कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। इमॅलियन आर जे

पूरी दुनिया टिकाऊ विकास और पर्यावरण-अनुकूल जीवशैली की ओर बढ़ रही है, तब भारतीय हथकरघा उद्योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ भी अपनी समृद्ध हथकरघा परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ के कोसा रेशम, पारंपरिक बुनाई और स्थानीय शिल्प देश-विदेश में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। यदि इन उत्पादों को आधुनिक डिजाइन, डिजिटल विपणन और राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाए, तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारिगरो के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए आमसझना का भी दिन है। हमें यह समझना होगा कि जब

एक एक हथकरघा उत्पाद खरीदते हैं, तब हम केवल एक वस्त्र नहीं खरीदते, बल्कि किसी बुनकर के परिवार को आजीविका, उसकी कला और उसकी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को भी सशक्त बनाते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश देता है। आइए, इस अवसर पर हम न केवल पूरे कि कि भारतीय हथकरघा उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, स्थानीय बुनकरों का सम्मान करेंगे और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित पहुँचाने में अपना योगदान देंगे। जिस राष्ट्र के हाथ हथकरघे पर सृजन करते हैं, उस राष्ट्र का भविष्य आत्मनिर्भरता, सम्मान और समृद्धि के रंगों से सदा अमूल्योत्कृष्ट रहता है।

स्नातकोतर के 46 विषयों में संशोधित पाठ्यक्रम लागू, वीकेएसयू में भी नए सत्र से होगी पढ़ाई

अधिसूचना के अनुसार यह नया पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा

प्रातः किरण संवाददाता

आरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप बिहार के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पीजी) के 46 विषयों का संशोधित पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। लोकभवन सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह नया पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा। इसका सीधा लाभ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू), आरा सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के पीजी विद्यार्थियों को मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत पीजी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया है। पाठ्यक्रम का निर्माण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक लचीली, कौशल आधारित और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन की भी सुविधा मिलेगी। संशोधित पाठ्यक्रम में आंबेडकर विचार, प्राचीन इतिहास, अंग्रेजी, अरबी, बंगाली, भोजपुरी,



बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बौद्ध दर्शन, रसायन विज्ञान, भौतिकी, वाणिज्य, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, गांधी दर्शन, भूगोल, धार्मशशास्त्र, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, इस्लामिक दर्शन, पत्रकारिता एवं जनसंचार, मगही, मैथिली, गणित, संगीत, पाली, फारसी, पर्सल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्राकृत, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, ग्रामीण अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, सांख्यिकी तथा उर्दू सहित कुल 46 विषय शामिल हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों को कुल 22 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। प्रत्येक पेपर

चार क्रेडिट का होगा और एक सेमेस्टर

में कुल छह पेपर पढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक पेपर 100 अंकों का होगा, जिसमें 70 अंक लिखित परीक्षा तथा 30 अंक इंटरनल असेसमेंट के निर्धारित किए गए हैं। किसी भी पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों को चार कोर कोर्स, एक जनरिक इलेक्टिव पेपर तथा एक वैल्यू एडेड या स्किल एन्हांसमेंट कोर्स का अध्ययन करना होगा। इससे विद्यार्थियों के ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल का भी विकास होगा।

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय,

आरा में भी नए शैक्षणिक सत्र से इसी संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप

पीजी की पढ़ाई कराई जाएगी।

वीकेएसयू में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

■ **एनएसएस के तत्वावधान में जीरो माइल परिसर में लगाए गए पौधे, कुलपति ने हरियाली बढ़ाने का किया आह्वान**
प्रातः किरण संवाददाता

आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू) के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के तत्वावधान में गुरुवार को विश्वविद्यालय के जीरो माइल परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन

किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा विश्वविद्यालय परिसर को अधिक हरित एवं स्वच्छ बनाना था। इस दौरान शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने पौधरोपण करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के



भावना, उत्तरदायित्व और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि वरीयता सूची का प्रकाशन प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर्मियों से जुड़े विभिन्न

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक



आरा। डीएम तनय सुल्तानिया के निर्देशानुसार आगामी 15 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय, जगदीशपुर में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह को गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए विभिन्न तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम, परेड, समारोह स्थल की साफ-सफाई, विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पोयजल, निबंध विद्युत आपूर्ति, आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आम नागरिकों एवं प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हों। अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, तरकारी आउटलेट निर्माण, पीएचईडी की जलमीनार एवं पाइपलाइन योजनाओं तथा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने सभी विभागों को आपसी सामन्वय के साथ जनहित की योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।



कराने का निर्देश दिया।

राजस्व विभाग की समीक्षा में अभियान बसेरा, व्यूटेरान, परिमार्जन और अन्य लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए विशेष शिविर

आफती बारिश:बरसात में टापू बना जगदीशपुर अनुमंडल कार्यालय

■ **तीन-चार दिनों से परिसर में भरा है बारिश का पानी, अधिकारियों, अधिकवक्ताओं और हजारों परियादिओं की बड़ी मुश्किलें; स्थायी जलनिकासी की मांग फिर तेज**

प्रातः किरण संवाददाता

जगदीशपुर।भोजपुर में लगातार हुई बारिश के बाद जगदीशपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर पिछले तीन-चार दिनों से जलजमाव की समस्या से जूझ रहा है। परिसर में बारिश का पानी जमा रहने के कारण अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकवाक्ताओं तथा दूर-दराज से आने वाले हजारों आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को पानी के बीच होकर कार्यालयों तक पहुंचना पड़ रहा है, जिससे प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों पर भी असर पड़ रहा है।

अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के अलावा एसडीपीओ कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, बार एसोसिएशन कार्यालय सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय संचालित होते हैं। यहां प्रतिदिन जगदीशपुर के साथ-साथ बिहिया और शाहपुर प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचते हैं। इनमें महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की भी अच्छी-खासी संख्या रहती है। जलजमाव के कारण सबसे अधिक परेशानी इन्हीं लोगों को उठानी पड़ रही है।



स्थानीय लोगों और अधिकवक्ताओं का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। हर वर्ष बारिश के मौसम में परिसर तालाब का रूप ले लेता है। कई बार अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया, लेकिन

अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। परिणामस्वरूप हर बारिश के बाद यही स्थिति दोहराई जाती है। बार एसोसिएशन के अधिकवक्ता वृंदानंद यादव ने बताया कि परिसर में माननीय न्यायाधीशों के साथ-साथ कई प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन बैठते हैं, लेकिन जलजमाव के कारण सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्षों से यह समस्या बनी हुई है। कई अधिकारी आए और स्थानांतरित होकर चले गए, लेकिन पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी। बरसात होते ही पूरा परिसर जलमग्न हो जाता है और लोगों को मजबूरी में पानी के बीच होकर आना-जाना पड़ता है।

एनईपी-2020 से विद्यार्थियों को अवगत कराने को ले महाराजा कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन

प्रातः किरण संवाददाता

आरा। महाराजा बहादुर राम रणजिजय प्रसाद सिंह कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग की ओर से गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों, कौशल-आधारित शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की

गई। कार्यक्रम कॉलेज की प्राचार्या डॉ. कनक लता के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। संगोष्ठी की अध्यक्षता रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. मंजू कुमारी ने की, जबकि संचालन एवं समन्वय की जिम्मेदारी डॉ. अंकिता ओझा ने निभाई। संगोष्ठी में डॉ. अरुण कुमार पांडेय, डॉ. राजलक्ष्मी, डॉ. संजीव रंजन, डॉ. राहुल कुमार मिश्रा, डॉ. जैस्मिन सिंह, डॉ. चंदन कुमार पासवान एवं डॉ. मंजुला सिंह ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं

पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि एनईपी-2020 विद्यार्थियों में नवाचार, शोध, व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली नीति है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार और उच्च शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। रूपाली कुमारी, काजल प्रिया, कुष्णा विश्वकर्मा, मनोज कुमार गुप्ता, प्रियंका कुमारी, कुनाल कुमार, अभिषेक कुमार, बलजीत आदि थे।

आरा सब्जी गोला के फुटकर सब्जी विक्रेताओं की बैठक संपन्न

फुटकर सब्जी विक्रेता संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया : वयामुद्दीन

प्रातः किरण संवाददाता

आरा। भाकपा माले राज्य स्थाई समिति सदस्य व आरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी क्यामुद्दीन अंसारी ने एक प्रसन्न बयान कर कर संवाददाताओं को बताया कि बीते रात आरा सब्जी गोला के सभी फुटपाथी सब्जी विक्रेताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई.इस बैठक में सैकड़ों फुटपाथी सब्जी विक्रेताओं ने हिस्सा लिया. इस बैठक में आरा सब्जी गोला उजाड़ने की सरकारी फरमान पर सब्जी विक्रेताओं के अंदर काफी

गम व गुस्सा देखने को मिला.

सब्जी विक्रेताओं की बैठक में गहन विचार विमर्श हुआ कि बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के मनमाने तरीके से उजाड़ने का तीखा विरोध किया जाएगा. इस बैठक में मौजूद भाकपा माले राज्य स्थाई समिति सदस्य व आरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी क्यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि सब्जी गोला में फुटपाथ से सब्जी बेचने वालों को सबसे पहले संगठित होना होगा तथा जिला प्रशासन के मनमाने ढंग से सब्जी गोला उजाड़ने के फरमान को तीखी आलोचना की.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के छह वर्ष पूर्ण होने पर एम.एम. महिला महाविद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन

प्रातः किरण संवाददाता

आरा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के छह वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाराजा महाविद्यालय महिला महाविद्यालय (एम.एम. महिला महाविद्यालय), आरा में कला एवं शिल्प (बेय्ट आउट ऑफ वेस्ट), पोस्टर निर्माण तथा निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया।कार्यक्रम में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचना प्रस्तुत की। कार्यक्रम का सफल आयोजन करने को बाध्य होगा।इतिहासकों ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी। डॉ उमेश राय, डॉ अशोक तिवारी, डॉ राधिका रमन, डॉ धनंजय प्रसाद राय, डॉ प्रेमलता, डॉ राकेश कुमार, डॉ अनंत कुमार सहित उपस्थित रहे।

दो बाइक की भिड़त में शिक्षक समेत दो जख्मी

आरा। आरा-पटना फोरलेन पर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा के समीप बुधवार की शाम दो बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शिक्षक समेत दो लोग जख्मी हो गए। गंभीर हालत में जख्मी शिक्षक को हाईवे एंबुलेंस डायल (1033) के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।सूचना पाकर परिजन भी सदर अस्पताल पहुंचे। जहां प्रार्थमिक उपचार के बाद उनकी चिंताजनक हालत को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। जानकारों के अनुसार जख्मियों में कोईलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव निवासी सूर्यनाथ सिंह के पुत्र सागर कुमार सिंह है। वर्तमान में वह नवादा थाना क्षेत्र के पकड़ौ मौहल्ले में किराए के मकान में रहते हैं।



नियंत्रक डॉ. मनोज कुमार, डॉ. स्मिता कुमारी, डॉ. अनुपमा तथा प्रॉक्टर डॉ. सादिया हबीब ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। डॉ. अनुपमा ने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर

अग्रसर रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावहारिक कौशल और शोध आधारित अध्ययन पर विशेष बल देती है, जिससे विद्यार्थी रोजगारोन्मुख और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बन सकें। कला एवं शिल्प प्रतियोगिता को आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर

लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर डीएम का

जोर, विभागों को दिए सख्त निर्देश



और एसटीपी परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। डीएम ने संचालित परियोजनाओं के प्रभावी संचालन तथा लंबित परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराकर कार्य प्रारंभ

आठ वर्षीय बच्चे की हत्या के प्रयास में पिता-पुत्र को उम्रकैद, एक-एक लाख का जुमाना

प्रातः किरण संवाददाता

बगहा। बगहा पुलिस जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में आठ वर्षीय अंकित यादव की गोली मारकर हत्या के प्रयास के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने गुरुवार को मुख्य आरोपित प्रमोद प्रसाद और उसके पुत्र बिल्लू प्रसाद उर्फ राहुल कुमार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मन्नु राव ने अदालत के समक्ष सात गवाहों की गवाही कराई। प्रस्तुत साक्ष्यों, चिकित्सीय रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने माना कि प्रमोद प्रसाद ने देशी



पिस्तौल से आठ वर्षीय अंकित यादव पर गोली चलाई थी, जबकि

बिल्लू प्रसाद उर्फ राहुल कुमार ने भी घटना में सक्रिय भूमिका निभाई

थी। अदालत ने दोनों को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया।मामले में

परिवर्तन जरूरी है के नारे के साथ भाकपा की पदयात्रा शुरू, संविधान बचाने से लेकर महंगाई-बेरोजगारी तक उठाई बुलंद आवाज

प्रातः किरण संवाददाता

बेतिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राष्ट्रीयपी आह्वान पर 6 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले पदयात्रा अभियान की शुरूआत पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड अंतर्गत भीतहा पंचायत से की गई। पदयात्रा भीतहां, बगही रतनपुर, बैरिया, मियापुर तिलंगहा, तधवानन्दपुर, लोकरिया और बथना पंचायत के विभिन्न गांवों से होकर निकाली गईं, जहां पार्टी नेताओं ने आम जनता के बीच पहुंचकर अपने संदेश और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा। पदयात्रा के दौरान भाकपा नेताओं ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा, बढ़ते



अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ व्यापक जनसमर्थन की अपील की। साथ ही अल्पसंख्यकों, दलितों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ करने, चारों लेबर कोड वापस लेने, गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाने, खाद

की कालाबाजारी समाप्त करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बहाल करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने की मांग को लेकर जनजागरण अभियान चलाया गया। इस पदयात्रा का नेतृत्व भाकपा जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति, जिला नेता राधामोहन यादव, अशोक मिश्र, बन्नु दुबे, चन्द्रिका प्रसाद, मनोज

संभावित बाढ़-सुखाड़ 2026: आपदा सहायता के लिए जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 24 घंटे सक्रिय

प्रातः किरण संवाददाता

बेतिया। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ -2026 को देखते हुए जिला प्रशासन, पश्चिम चम्पारण ने आमजनों की सहायता एवं आपदा संबंधी सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए जिला स्तर पर जिला आपातकालीन संचालन केंद्र बेतिया को 24 घंटे (24x7) संचालित रखा है। प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा नगमा तबस्सुम ने जिला प्रशासन ने कहा कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, बाढ़, जलजममाव, सुखाड़ अथवा अन्य

आपदा संबंधी सूचना, सहायता या राहत कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए आम नागरिक किसी भी समय संचालन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी आपदा संबंधी सूचना को तत्काल जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के दूरभाष 06254-247002 एवं मोबाइल: 8757547904 पर उपलब्ध कराएं, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

अनुदान में मिली सामग्री बेचने के आरोप में तीन गिरफ्तार सरकारी योजना के दुरुपयोग का मामला उजागर



प्रातः किरण संवाददाता

बगहा । नेपाल पुलिस ने सरकार की ओर से अनुदान के तहत वितरित की गई सामग्री की अवैध रूप से बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों ने लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई अनुदान सामग्री को बाजार में बेचकर निजी लाभ कमाने का प्रयास किया। मामले की सूचना मिलने के बाद

संबंधित निकाय और पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सरकारी अनुदान का उद्देश्य किसानों और वास्तविक लाभार्थियों को राहत पहुंचाना था, लेकिन आरोपियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सामग्री की खरीद-बिक्री की। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं और पात्र लाभार्थियों के अधिकारों का हनन करती हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में अन्य लोगों या किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता तो नहीं है। संबंधित सरकारी कार्यालय से वितरण अभिलेख और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर जांच की जा रही है।

ओएचई इंसुलेटर हुक टूटने से दो घंटे टप रहा रेल परिचालन, पनिअहवा में खड़ी रही वंदे भारत

बगहा। गोरखपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर बगहा और खैरोपेखरा स्टेशन के बीच स्थित पुल संख्या-349 के पास गुरुवार सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) लाइन का इंसुलेटर हुक टूट जाने से करीब दो घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। तकनीकी खराबी के कारण गोरखपुर से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को पनिअहवा स्टेशन पर रोकना पड़ा, जबकि नरकटियागंज जंक्शन से गोरखपुर कैट जाने वाली दैनिक पैसंजर ट्रेन संख्या 55097 खैरोपेखरा स्टेशन पर करीब दो घंटे तक खड़ी रही। तकनीकी खराबी के चलते इस रेलखंड से गुजरने वाली कई अन्य यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों को भी विभिन्न स्टेशनों पर रोकना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ बगहा के पोस्ट प्रभारी इंद्रजीत सिंह मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी रेलवे के वरीय अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही नरकटियागंज से रेलवे की तकनीकी टीम टावर वैगन के साथ घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने क्षतिग्रस्त इंसुलेटर की मरम्मत का कार्य शुरू किया और आवश्यक तकनीकी सुधार के बाद ओएचई लाइन को पुनः चालू कर दिया। इसके बाद रेल परिचालन धीरे-धीरे सामान्य हो गया।

नामजद अन्य आरोपित गुड्डू प्रसाद, कौशल्या देवी और मुखी देवी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने सदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया। निर्णय सुनाते हुए अदालत ने प्रमोद प्रसाद और बिल्लू प्रसाद उर्फ राहुल कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त प्रमोद प्रसाद को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुमाना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही, न्यायालय ने आदेश दिया कि जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन नियमानुसार किया जाएगा।

मोतिहारी। जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंह के साथ सदर अंचल मोतिहारी का औचक निरीक्षण निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अंचल अधिकारी,राजस्व अधिकारी सहित अन्य कर्म उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान दाखिल- खारिज, परिमार्जन, एलपीसी प्रमाण पत्र, सरकारी भूमि अतिक्रमणवाद की समीक्षा की गई और आरटीपीएस काउंटर की जांच की गई। आरटीपीएस काउंटर पर जांच के दौरान प्राप्त आवेदनों एवं निष्पादित आवेदनों के संधारण को देखा गया एवं इससे संबंधित जरूरी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के द्वारा दाखिल-खारिज के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए एक सप्ताह का समय दिया गया। सरकार के विकास कार्यों हेतु जमीन

जिलाधिकारी ने किया सदर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण

प्रातः किरण संवाददाता

रक्सौल। प्रखंड क्षेत्र के भेलाही स्थित नथुनी दुर्गा हाई स्कूल परिसर में गुरुवार को प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्राण रंजन प्रसाद ने की। बैठक को संबोधित करते हुए बीईओ श्री प्रसाद ने कहा कि जिले में लगभग तीन लाख छात्र-छात्राएं अभी तक अपार आईडी से वंचित हैं। इनमें करीब 37 हजार विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, जबकि लगभग 2 लाख 63 हजार छात्रों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया कि आधार विहीन विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क कर शीघ्र आधार कार्ड बनवाना



आवंटन में तेजी के निर्देश दिये गए। अंचल कार्यालय निरीक्षण के दौरान अंचल पंजी के संधारण में कमी पाई

गई। इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर अभिलेखों को अपडेट करने के निर्देश दिए गए।

आधार विहीन विद्यार्थियों का जल्द बनवाएं आधार शत-प्रतिशत तैयार करें अपार आईडी : बीईओ

प्रातः किरण संवाददाता

सुनिश्चित करें, ताकि सभी बच्चों को अपार आईडी समय पर तैयार हो सके।उन्होंने केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत प्रशस्त ऐप पर शत-प्रतिशत पंजीकरण करने, विद्यालयों में उपस्थिति पंजी का सुव्यवस्थित संधारण तथा फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) में सभी शिक्षकों की प्रविष्टि समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही नवीदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थियों का आवेदन भरवाने पर जोर देते हुए जन्मतिथि का निर्धारित मानकों के अनुसार सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान विभागीय दिशा-निर्देशों, शैक्षणिक गतिविधियों तथा विद्यालय संचालन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कई प्रधानाध्यापकों ने विद्यालयों की समस्याओं से भी बीईओ को

अवगत कराया, जिस पर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। बैठक में डाटा एंट्री ऑपरेटर मनोज कुशवाहा, शिक्षक मनोप कुमार के अलावा प्रधानाध्यापक छोटेलाल राय, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार, गोपाल प्रसाद,मुनेश राम, बृज किशोर प्रसाद, विद्या बाबू, जितेंद्र शाह, जवाहरलाल प्रसाद, कुंदन कुमार, प्रियंका कुमारी, इंदु कुमारी, विनय कुमार सिंह, मदन प्रसाद यादव, कृष्ण कुमार, कृष्ण सिंह, अरविंद कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, कृष्ण मोहन श्रीवास्तव, राकेश कुमार आर्य, रमेश कुमार, वेदप्रकाश शर्मा, रौनक, सीमा देवी, टुनटुन लाल गुप्ता, संदीप कुमार जायसवाल, अशोक कुमार, सिद्धेश्वर आर्य, ज्योति गुप्ता, अनिता कुमारी सहित प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक उपस्थित रहे।

मोतीपुर सरेह में बाघ के शावक जैसी वन्यजीव की आहट से दहशत, वन विभाग अलर्ट

प्रातः किरण संवाददाता

बगहा। रामनगर प्रखंड के मोतीपुर सरेह में मंगलवार को खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों के बीच उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक जंगली जानवर, जिसे ग्रामीणों ने बाघ का शावक बताया, खेत की ओर आता दिखाई दिया। जानवर को देखते ही खेत में काम कर रही महिलाएं और अन्य ग्रामीण अपनी सुरक्षा के लिए वहां से हट गए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया ग्रामीणों ने बताया कि वे रोज की तरह खेतों में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक शावक जैसा एक वन्यजीव दिखाई दिया, जो कुछ देर तक खेत

के आसपास घूमता रहा। इसके बाद इसकी सूचना आसपास के गांवों में फैल गई, जिससे मोतीपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग सतर्क हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया है। वन संरक्षक सह निदेशक गौरव ओझा ने बताया कि विभागीय टीम को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के आधार पर यह भी संभव है कि ग्रामीणों को जो वन्यजीव दिखाई दिया, वह बाघ का

शावक नहीं बल्कि फिशिंग कैट हो, जो आकार और रंग-रूप के कारण दूर से बाघ के बच्चे जैसी प्रतीत होती है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वन्यजीव के दिखने पर किसी से संपर्क न करें, उसे घेरने या भगाने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें तथा अफवाहों पर ध्यान न देकर सतर्कता बरतें। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल बना लायंस क्लब ऑफ रक्सौल

रक्सौल। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक पहल करते हुए लायंस क्लब ऑफ रक्सौल ने लायन सत्र 2026झ2027 के लिए क्लब के तीनों प्रमुख पद—अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष—पर महिलाओं का चयन कर समाज के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक सादगीपूर्ण एवं गरिमामय समारोह में पूर्व अध्यक्ष लायन बिमल सर्राफ ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायन प्रियंका सोनी को विधिवत पदभार सौंपा। वहीं लायन सीमा बर्णवाल ने सचिव तथा लायन डॉ. भावना चौहान ने कोषाध्यक्ष का दायित्व ग्रहण किया। यह समारोह पूर्व अध्यक्ष लायन गणेश धानोठिया के आवास पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर संस्थापक सदस्य पूर्व अध्यक्ष लायन बिमल सर्राफ,पूर्व अध्यक्ष लायन शंभु प्रसाद चौरसिया, लायन नारायण रूग्ठा, लायन गणेश धानोठिया, लायन पंकज बर्णवाल, पूर्व सचिव लायन पवन किशोर कुशवाहा, पूर्व कोषाध्यक्ष लायन अमित कुमार, लायन संजय गुप्ता तथा लायन सुशीला धानोठिया सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान में लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322ई के जोनल चेयरपर्सन सह डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन बिमल सर्राफ ने नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ह्लायांस क्लब ऑफ रक्सौल ने सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मुझे विश्वास है कि नई टीम अपने समर्पण, नेतृत्व और सेवा भावना से क्लब को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाएगी तथा समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करेगी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लायन प्रियंका सोनी ने कहा कि वे सभी सदस्यों को साथ लेकर लायंस इंटरनेशनल के मूल मंत्र वी सर्व ('हम सेवा करते हैं') को ज्ञान-तक पहूँचाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेंगी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में क्लब की गतिविधियों को और अधिक प्रभाव बनाते का संकल्प भी व्यक्त किया। आज जब देशभर में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने की बात हो रही है, ऐसे समय में लायंस क्लब ऑफ रक्सौल द्वारा तीनों शीर्ष पदों पर महिलाओं को नेतृत्व सौंपना ने केवल क्लब के लिए गौरव का विषय है, बल्कि समाज में समान अवसर, महिला सम्मान और सशक्त नेतृत्व का एक सशक्त संदेश भी है। यह जानकारी क्लब के मीडिया प्रभारी लायन बिमल सर्राफ ने प्रेस को दी।

बर्दिबास में बिजली ट्रांसफार्मर चोरी, कई बस्तियों को बिजली आपूर्ति बाधित

बगहा। नेपाल के महोत्तरी जिले के बर्दिबास क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मर चोरी की घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। अज्ञात चोरों ने रात के समय विद्युत लाइन पर लगे ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया और उसके भीतर मौजूद तांबे की कॉयल तथा अन्य कीमती उपकरण निकालकर फरार हो गए। घटना के बाद कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि सुबह निम्नित निरीक्षण के दौरान ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला। प्रारंभिक जांच में चोरी की पुष्टि होने के बाद इलाका प्रहरी कार्यालय, बर्दिबास को सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के महीनों में बर्दिबास क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है।इससे पहले भी मोटरसाइकिल चोरी और अन्य अपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके कारण लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।



जिला पदाधिकारी ने भूमि विवाद से संबंधित मामले को न्यायालय के माध्यम से जल्द निर्णय कराने का दिया निर्देश

प्रातः किरण संवाददाता

मुंगेर। जिला समन्वय समिति एवं राजस्व की मासिक समीक्षा बैठक गुरुवार संग्रहालय सभागार में जिलाधिकारी निखिल धनराज निम्पाणीकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, उनकी वर्तमान प्रगति, लंबित मामलों तथा राजस्व संग्रह की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मनरेगा डीपीओ के कार्यकलापों पर असंतोष व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण करते हुए उनके वेतन स्थगन के निदेश दिए गए। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर उनसे कारण पृच्छा सहित अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों के वेतन पर रोक लगाने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। मौके पर अपर समाहर्ता मनोज कुमार, नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता, अपर समाहर्ता (आपदा) संजय कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी



उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की विभागावार समीक्षा करते

हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान करने, निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने तथा योजनाओं की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष बल दिया। खेल मैदान, जीविका ग्राम संगठन, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु स्थल चयन करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शीघ्र इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की विभागावार समीक्षा करते

विभाग, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, उर्जा विभाग सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की गयी, जिसमें जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसकी प्रगति पर विशेष ध्यान देने एवं सभी कार्या को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों के निष्पादन में संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों में गति लाने तथा प्रशासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सहयोग पोर्टल पर जितने भी लंबित आवेदन हैं, उसका स-समय निष्पादन करना सभी विभागों का दायित्व है। जिन भी अधिकारियों के लॉगिन में सहयोग पोर्टल के मामले लंबित हैं, उसका शीघ्र निष्पादन करें, ताकि मामले लंबित परिलक्षित न रहे। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा

है, इस लिए इसके प्रति सजग एवं सचेत होकर कार्य करें। राजस्व से संबंधित समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व संग्रह में अपेक्षित प्रगति लाने, लंबित राजस्व वसूली मामलों का त्वरित निष्पादन करने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह से जुड़े सभी मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विवाद न हो। उन्होंने दाखिल खारिज के मामले में जमालपुर, खड़गपुर एवं सदर प्रखंड में अधिक मामले लंबित रहने पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसमें सुधार लाने के निदेश दिए। इसके अलावे परिमार्जन प्लस, डिजिटाइज्ड जमाबंदी, ई-मापी, राजस्व महाअभियान से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामलें विभिन्न न्यायालयों में लंबित दिख रहे हैं, इसमें कमी लाने की जरूरत है। इस लिए सभी संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से अपने अपने न्यायालय में लंबित पड़े मामलों के निष्पादन में गति लाएं।

एसटीईटी अभ्यर्थियों की जायज मांगों पर सरकार तत्काल निर्णय ले : लोकमंच

प्रातः किरण संवाददाता

भारतीय लोकमंच पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कुणाल सिकंद ने बिहार सरकार एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आग्रह किया है कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 अभ्यर्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करते हुए उनकी जायज मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में युवाओं की शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। केवल विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती और बैरिकेडिंग कर देना इस समस्या का समाधान नहीं है। वास्तविक समाधान बनी अनिश्चितता समाप्त करें।

साँक्षिप्त खबरें

हड़ताल समाप्त, गया नगर निगम

ने सफाईकर्मियों से की शहर को

फिर से चमकाने की अपील

गयाजी। नगर निकायों में पिछले एक सप्ताह सेजारी हड़ताल गुरुवार को सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच हुई सफल वार्ताके बाद उमाम हो गई। हड़ताल खत्म होने के साथ ही गया नगर निगम प्रशासन ने सभी सफाईकर्मियों एवं अन्य कर्मियों से तत्काल अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू करने और पूरे शहर मेंविशेष सफाई अभियान चलाने की अपील की है।शेाहर में हड़ताल के दौरान प्रभावित हुई सफाई व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नगर निगम की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि शहर के विभिन्न वार्डों, मुख्य सड़कों, गलियों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जमा कूड़े-कचरे का तत्काल उठाव किया जाए। सभी सफाईकर्मियों से आग्रह किया गया है कि वे पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ सफाई कार्य में जुटें, ताकि शहर को जल्द से जल्द स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाया जा सके। साथ ही नियमित रूप से झाड़ू लगाने, कचरा संग्रहण एवं गलियों की सफाई का कार्य भी पूर् की तरह सुचारु रूप से संचालित किया जाए। नगर निगम ने कहा है कि गया विश्वप्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन नगरी है और आगामी माह से शुरू होनेवाला विश्वप्रसिद्ध पितृपक्ष मेला शहर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। इस दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पिंडदान एवं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आया पहुंचते हैं। इसे में स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर की छवि बनाए रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से सफाई व्यवस्था को पूरी क्षमता के साथ बहाल करने की दिशा में पहल की जा रही है। प्रशासन ने सभी सफाई निरीक्षकों, वार्ड प्रभारियों एवं संबंधित अधिकारियों से भी अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई अभियान की सतत निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी कूड़े का जमाव न रहे। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधनों और वाहनों की मदद से भी सफाई कार्य को गति देने की बात कही गई है, ताकि कम समय में पूरे शहर की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर लौट सके। नगर निगम ने शहरवासियों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें, खुले में कूड़ा फेंकने से बचें तथा स्वच्छता बनाए रखने में नगर निगम का साथ दें। नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि सफाई कार्य अत्यावश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है।

तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर: 70 वर्षीय वृद्ध को मारी जोरदार टक्कर, चालक वाहन समेत फरार



प्रातः किरण संवाददाता

धरहरा (मुंगेर)। धरहराझु वसौनी मुख्य मार्ग पर गुरुवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक 70 वर्षीय वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में धरहरा निवासी विनोद सिंह चौहान गंभीर रूप से घायल

हो गए। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना लक्ष्मी पुस्तकालय के समीप हुई। तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने सामने से वृद्ध को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे सड़क

पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। स्थानीय लोगों की तत्परता से घायल विनोद सिंह चौहान को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धरहरा पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद फरार चालक की तलाश की मांग तेज हो गई है। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान कर चालक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि धरहराझुवसौनी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए प्रशासन को इस मार्ग पर यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

सावन के आठवें दिन साढ़े तीन लाख कांवड़िया अजगैविनाथ धाम से बैधनाथ धाम के लिए हुए रवाना



प्रातः किरण संवाददाता

भागलपुर सुल्तानगंज। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के आठवें दिन साढ़े तीन लाख कांवड़िया अजगैविनाथ धाम से बैधनाथ धाम के लिए हुए रवाना/आपको बताते चलें कि बिहार, झारखंड, राजस्थान उत्तरप्रदेश बंगाल नेपाल, उड़ीसा के हजारों हजारों की संख्या में सुबह से ही उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर गंगा में डुबकी लगाने की भीड़ उमड़ गई थी/कांवड़ियों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर हर हर महादेव,बोल बम के जयाकारे



आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। विधायक ने विश्वास जताया कि यह परियोजना निर्धारित समय-सीमा में पूरी होकर मुंगेर वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

उच्च मध्य विद्यालय बीटी विगहा श्रीरामपुर में इको क्लब के तत्वावधान में हुआ पौधारोपण

प्रखंड क्षेत्र के उच्च मध्य विद्यालय बीटी विगहा श्रीरामपुर में गुरुवार को इको क्लब के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विद्यालय के इको क्लब के नोडल शिक्षक बृजेश कुमार पांडेय ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा हरियाली को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व विधायिका मंजू अग्रवाल थीं। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य विजय गुप्ता एवं कर्मलेश प्रसाद सिंह सहित अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में विद्यालय परिसर में छायादार एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी पौधों का रोपण किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान शिक्षकों में स्वाती कुमारी, निलेश कुमार, शशि श्रीवास्तव, संजीत यादव, रंजीत, रामप्रवेश सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सभी ने मिलकर विद्यालय परिसर को हराभरा बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए।इको क्लब के नोडल शिक्षक बृजेश कुमार पांडेय ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं। ये न केवल लक्ष्य वायु और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने तथा लगाए गए पौधों की सुरक्षा और नियमित देखभाल का सामूहिक संकल्प लिया।

मुंगेर। मुंगेर शहर के लिए बड़ी राहत की खबर है केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत मुंगेर जलापूर्ति परियोजना फेज-1 के लिए 177.72 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार प्रणय ने इस स्वीकृति को जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मुंगेर शहर में स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था और मजबूत होगी। वर्षों से बेहतर जलापूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हजारों नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और शहर के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और विकासोन्मुखी कार्यशैली की कारण बिहार के शहरों में मुंगेर जलापूर्ति परियोजना को तेजी से विस्तार हो रहा है। विधायक ने विश्वास जताया कि यह परियोजना निर्धारित समय-सीमा में पूरी होकर मुंगेर वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

धरहरा में जनगणना 2027 की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, पारदर्शिता और शुद्धता पर जोर

प्रातः किरण संवाददाता

धरहरा (मुंगेर)। जनगणना 2027 की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में गुरुवार को धरहरा प्रखंड कार्यालय सभागार में जिला जनगणना पुस्तिका (डीसीएचबी) के अंतर्गत फील्ड पदाधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों को शत-प्रतिशत सटीक आंकड़ों के संकलन, अभिलेखों के सत्यापन तथा निर्धारित प्रारूप के अनुसार सूचनाएं संग्रहित करने की प्रक्रिया से दक्ष बनाना था। प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षक राजीव कुमार झा ने जनगणना की कार्यप्रणाली, डेटा संकलन, रिकॉर्ड संधारण तथा विभिन्न प्रपत्रों को सही ढंग से भरने की विस्तृत जानकारी दी। वहीं टी.ए. (जनगणना) प्रिंस राज ने तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में फील्ड पदाधिकारी मनोज कुमार, कपिल देव दास, सतीश कुमार, एमडी वसीम, राज कुमार दास एवं सत्येन्द्र नारायण सिंह सहित अन्य कर्मियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने जनगणना कार्य में गोपनीयता, पारदर्शिता और शुद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया। प्रशिक्षकों ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि देश के भविष्य की विकास योजनाओं की आधारशिला है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आवास, रोजगार और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है तथा संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करती है। उन्होंने सभी फील्ड पदाधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सतर्कता और निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया, ताकि जनगणना 2027 का कार्य पूरी तरह विश्वसनीय, प्रभावी और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

